आज का विचार

याद रखें बुरा वक्त हमें यह जरूर सिखाता है कि अच्छा वक्त किसके साथ बिताना है।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । मंगलवार, 17 जून, 2025 वर्ष 23, अंक 148, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

मोदी की साइप्रस यात्रा से रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा, एक्शन प्लान तैयार करने पर सहमति बनी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा ने भारत की वैश्विक कूटनीति को नई दिशा दी है। अपनी दो दिवसीय यात्रा (15-16 जून) के दौरान प्रधानमंत्री ने साइप्रस की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए 2025 से 2029 तक की एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने पर सहमति बनी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स के साथ आज औपचारिक वार्ता की। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। एक दिन पहले राष्ट्रपति स्वयं एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे थे। यह दोनों देशों की गहरी मित्रता को दशार्ता है।दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा और भारत के साथ एकजुटता के लिए साइप्रस का आभार जताया। साथ ही उन्होंने साइप्रस की एकता और साइप्रस प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।

उन्होंने व्यापार, निवेश, स्टार्टअप, रक्षा, फिनटेक, एआई, साइबर व समुद्री सुरक्षा सहित सहयोग के नए क्षेत्रों पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग के लिए पांच वर्षीय रोडमैप बनाने का निर्णय लिया। रक्षा साझेदारी को मजबूती देने वाले जनवरी 2025 के समझौते की भी सराहना की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) को क्षेत्रीय शांति व समृद्धि का वाहक बताया। संयुक्त राष्ट्र सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता पर साइप्रस के समर्थन के लिए उन्होंने राष्ट्रपति का धन्यवाद किया।

भारत और साइप्रस ने संयुक्त घोषणा में इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) को एक रणनीतिक और परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में पहचाना। यह गलियारा भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ते हुए व्यापार, संपर्क और टिकाऊ विकास को नया आयाम देगा। साइप्रस को यूरोप का प्रवेश द्वार मानते हुए दोनों पक्षों ने इसे एक क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। भारतीय शिपिंग कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया।

दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहगाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की।अगले साल यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने जा रहे साइप्रस ने भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का वादा किया। दोनों पक्षों ने 2025 तक ईयू-भारत मुक्त व्यापार समझौते के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलाइड्स ने सांस्कृतिक और जन-संपर्क को रणनीतिक संपत्ति मानते हुए एक मोबिलिटी पायलट प्रोग्राम की घोषणा की। सीधे हवाई संपर्क और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की शुरूआत की गई।

दरअसल, साइप्रस का राजनीतिक और क्षेत्रीय विवाद 1974 में तुर्किये द्वारा साइप्रस के उत्तरी भाग पर सैन्य कब्जे के बाद उपजा था। इसके चलते द्वीप अब दक्षिण में यूनानी साइप्रस और उत्तर में तुर्किये प्रभावित उत्तर साइप्रस तुर्की गणराज्य के रूप में बंटा है, जिसे केवल तुर्किये मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र इसे एक विभाजित राष्ट्र मानता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महापौरों को बताया शहरों के विकास का सारथी

पंचकूला में अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक का आयोजन

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापौर अपने-अपने शहरों के प्रथम नागरिक होने के साथ-साथ वहां के विकास और प्रगति के प्रत्यक्ष सारथी भी हैं। उन्होंने कहा कि महापौर सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, नागरिकों की आकांक्षाओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना में महापौर रीढ़ के समान हैं। मुख्यमंत्री श्री सैनी आज पंचकूला में आयोजित अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महापौर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। यह व्यवस्था नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच मजबूत सेतु बनाती है और निर्णय प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह तथा प्रभावी बनाती है। उन्होंने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब शहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। शहर केवल निवास स्थान नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास के इंजन, नवाचार के केंद्र और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संगम हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम अर्बनाइजेशन को चुनौती नहीं, अवसर मानते हैं। हमारा विजन है कि शहर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संगम बनें। हमें शहरों को केवल इमारतों और सड़कों का ढांचा नहीं बनाना, बल्कि उन्हें जीवंत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भी बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की लगभग 900 मिलियन आबादी शहरों में निवास करेगी। यह सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी संभावना है। नए अवसरों, नए इन्फ्रास्ट्रक्चर और नई जीवनशैली की। हमें इस परिवर्तन को सुनियोजित शहरीकरण, डिजिटल एकीकरण और पर्यावरण संरक्षण के साथ अपनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 5,666 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चार मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं और फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत फरीदाबाद में 930 करोड़ रुपये की लागत से 45 परियोजनाएं तथा करनाल में 927 करोड़ रुपये की लागत से 122 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है और नई अधिकृत कॉलोनियों में एक हजार करोड़ रुपये से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत मिशन के तहत अब तक 2,930 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 375 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लक्ष्य में से 9 शहरों में 50 बसें चलाई जा चुकी हैं और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 2026 तक 450 बसें खरीदी जाएंगी।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 21,431 मकान बनाए जा चुके हैं और 11,412 मकान निमार्णाधीन हैं।

मोदी के नेतृत्व में भारत ने की अभूतपूर्व प्रगति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 11 वर्षों में अद्वितीय प्रगति की है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। आज भारत 2025 तक चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है और 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वह निश्चित रूप से साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महापौर और अध्यक्ष के चुनाव सीधे करवा कर उनकी प्रतिष्ठा और विकास की गति को बढ़ाने का कार्य किया है। अंत्योदय की भावना के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सभी महापौरों को और अधिक जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग की सराहना करते हुए कहा कि मेयर और पार्षदों को इंदौर जाकर वहां की योजनाओं और मॉडल का अध्ययन करना चाहिए ताकि हरियाणा के शहरों में भी उसी प्रकार के मॉडल लागू किए जा सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं की सफलता में महापौरों की भूमिका की सराहना की और कहा कि इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य महापौरों द्वारा ही होता है।

पिछले 10 वर्षों में एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई ने भारत को आपदा प्रबंधन में वैश्विक नेता बनने के करीब पहुंचाया : अमित शाह

90 दिन में जिला आपदा प्रबंधन की योजना बनाने का निर्देश दिया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने के करीब पहुंचा दिया है।

केन्द्रीय मंत्री राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों तथा आपदा मोचन बलों के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने राहत आयुक्तों से कहा कि कई सारे जिलों में आपदा प्रबंधन योजना बनानी बाकी है। क्या हम तय कर सकते हैं कि यहां से जाने के बाद 90 दिन में प्रत्येक राज्य में हर जिला की आपदा प्रबंधन योजना बनाने का काम समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक जिला की आपदा प्रबंधन योजना नहीं होगी तब तक आपदा से तेजी से लड़ना संभव नहीं है। आकाशीय बिजली से निपटने के उपायों को लेकर उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि आकाशीय बिजली से लोगों को बचाना संभव नहीं लेकिन आज विज्ञान बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने इस पर कार्य योजना बनाकर 90 दिनों में केन्द्र के साथ साझा करने का निर्देश दिया। शाह ने ओला गिरने और शीत लहर को लेकर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की कार्य योजना नहीं बनने पर भी चिंता जताई।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि हमें आपदा से लड़ने की तैयारी तो करनी ही है साथ ही आपदा के कारणों के मूल में भी जाना होगा।

उन्होंने जलवायु परिवर्तन को आपदा का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार ने जो काम किया है, वह अतुलनीय है। आपदा से बचाव के बारे में सोचना अधूरा दृष्टिकोण है। समग्र दृष्टिकोण में ऐसी पृथ्वी का निर्माण शामिल है, जहां कोई आपदा न हो। हमें इस दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाना चाहिए। अगर हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम आपदा से खुद को नहीं बचा सकते।

अमित शाह ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया आपदाओं को लेकर चिंतित है। लेकिन हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि मात्र 10 वर्षों में एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने के करीब पहुंचा दिया है। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव गोविन्द मोहन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य और विभागाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह, आपदा प्रबंधन के अपर सचिव संजीव कुमार जिंदल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के महानिदेशक पीयूष आनंद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान मौजूद थे।

प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस क्क्कप्रदान किया। यह सम्मान उन्हें दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सहयोग के प्रतीक के रूप में दिया गया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर फोटो साझा करते हुए इसे भारत-साइप्रस मैत्री और साझी वैश्विक दृष्टि का सम्मान बताया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच स्थायी और विश्वसनीय संबंधों का प्रमाण है। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति, सरकार और जनता के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान भारत की प्राचीन सोच वसुधैव कुटुंबकम्को मिली वैश्विक मान्यता है, जो शांति और समृद्धि की दिशा में हमारे प्रयासों को प्रेरित करती है।

प्रधानमंत्री ने इसे भारत-साइप्रस संबंधों को और मजबूत व बहुआयामी बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों की शांति, संप्रभुता और विकास के प्रति साझा निष्ठा को दशार्ता है।

जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम : भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

जातिगत जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि मोदी सरकार के जरिए जातिगत जनगणना का निर्णय एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि जनगणना का फॉर्म भरते समय मुसलमान अपनी जाति की सही जानकारी दें और कट्टरपंथी मौलानाओं के बहकावे में नहीं आएं, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के भीतर मौजूद जातियों की भी विस्तृत गिनती की जाएगी। अब तक मुस्लिमों को केवल एक धार्मिक समूह के रूप में दर्ज किया जाता रहा है, जिससे उनके भीतर की सामाजिक और आर्थिक विविधताओं पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस जनगणना से मुस्लिम समुदाय की जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से जुड़े ठोस आंकड़े सामने आएंगे, जो नीति निर्माण और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं।

जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पसमांदा मुसलमान मुस्लिम कट्टरपंथियों के बहकावे में न आएं और अपनी जाति की सही जानकारी उपलब्ध कराएं क्योंकि कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं द्वारा गुमराह करने के लिए लोगों से अपील की जा रही की जातिगत जनगणना के दौरान मुस्लिम अपनी जाति इस्लाम बताएं। जबकि यह जातिगत जनगणना है, धार्मिक जनगणना नहीं। जाति संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति में जातियां होती हैं जिसके द्वारा मुस्लिम समाज के भीतर भी जातिगत विविधताओं को सामने लाया जाएगा, तो उस एकरूपता की धारणा टूटेगी। इस पहल का सबसे बड़ा असर पसमांदा मुस्लिम समुदाय पर पड़ सकता है। मुस्लिम समाज में भी 85 फीसद जनसंख्या पसमांदा मुसलमानों की है, जो पिछड़े हुए हैं, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। लेकिन ठोस आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है।

हमारा उददेश्य सत्ता प्राप्ति नहीं, जनता की सेवा है, हमने अपने विचारों से समझौता नहीं किया: रक्षा मंत्री

जनता की सेवा हमारे डीएनए में, हम जनसेवक हैं शासक नहीं : राजनाथ सिंह

एजेंसी (हि.स.)
भोपाल/पचमढ़ी

सभी सांसद और विधायक हमेशा संगठन से जुड़े रहें, क्योंकि संगठन तब भी था जब सत्ता नहीं थी। कार्यकताओं को सम्मान दें और उनकी बात सुनें क्योंकि भाजपा की असली ताकत जनता का भरोसा और कार्यकताओं का परिश्रम ही है। जनता की सेवा हमारे डीएनए में है, हम जनसेवक हैं शासक नहीं। जनता का भरोसा और कार्यकताओं का परिश्रम ही भाजपा की असली ताकत है। जनता का भरोसा जीतें और हर संकट के समय सबसे पहले जनता के बीच पहुंचें। महापुरूषों की विचारधारा को आगे बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं, जनता की सेवा है, इसलिए हमने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं इसलिए भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण और विचारधारा सबसे प्रथम है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पचमढ़ी में आयोजित तीन दिवसीय भाजपा सांसद एवं विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की परंपरा सतत और प्राचीन है। यह पार्टी की कार्यशैली का अंग है। आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी एक अलग पहचान है। लेकिन पार्टी की इस विकास यात्रा में तीन चीजें नहीं बदलीं। ये हैं- प्रशिक्षण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण की भावना। यह प्रशिक्षण वर्ग आप सभी के लिए पार्टी की वैचारिक यात्रा को समझने और आत्मसात, आत्मचिंतन करने का अवसर है। श्रद्धेय अटलजी ने कहा था कि सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रसेवा होना चाहिए। हमारी जिस वैचारिक यात्रा का शुभारंभ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय ने किया था वह आज भी जारी है। हमारे लिए राजनीति राष्ट्रनिर्माण का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी यह यात्रा आज भी चल रही है और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन हमने अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हमारी नीयत और नीतियां आज भी वही हैं। हम अपने मूल विचार से भटके नहीं हैं। भाजपा आज जहां पहुंची है, उसमें हमारे पूर्वजों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पं.दीनदयाल जी ने हमें एकात्म मानववाद दिया, श्रद्धेय अटलजी ने हमें संयम सिखाया और श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यह प्रशिक्षण वर्ग इसी संकल्प को पुष्ट करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा राष्ट्र प्रथम की रही है। पं. दीनदयाल चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अपने विचारों, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आप कभी ऐसा आश्वासन न दें, जो पूरा न किया जा सकता हो और सिद्धांतों से समझौता न करें।

राजनाथ सिंह ने कहा कि विकसित भारत हमारा लक्ष्य नहीं, बल्कि संकल्प है। भारत को आत्मनिर्भर, समावेशी और गौरवशाली राष्ट्र बनाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। देश आज सुरक्षित है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 11 वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचने जा रही है और ये बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि बदलाव जमीन पर दिखाई देता है। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में अब हम एक निर्यातक देश के रूप में उभर रहे हैं। भारत अपनी संप्रुभता और अखंडता की रक्षा करने में कोई समझौता नहीं करेगा, हमने यह ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है।

हिमाचल में नशा और खनन माफिया की संपत्ति होगी ध्वस्त: सुखविंदर सुक्खू

सीएम सुक्खू का ऊना से ऐलान, बोले संरक्षण देने वाले भी जाएंगे जेल

एजेंसी (हि.स.)
ऊना

अब देवभूमि हिमाचल में भी नशे के सौदागरों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। यह ऐलान सीएम ठाकुर सुक्खबिंद्र सिंह सुक्खू ने ऊना में अवैध खनन और चिट्टा माफिया पर बड़ा हमला बोलते हुए किया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन व चिट्टा माफिया को लेकर कई सूचनाएं एंजेसियों से सरकार को प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध मामलों में चाहे कोई कर्मचारी हो या कोई अन्य हो उसे किसी भी स्तर पर बख्शा नही जाएगा। नशे के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है।मुख्यमंत्री ने खुले मंच से खनन और चिट्टा माफिया को कुचलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस खुलेहाथ से ऐसे लोगों के माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करे जो आमजन को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे को बढ़ावा देने वालों की प्रॉपटी जब्त होगी। वहीं चिट्टा माफिया को संरक्षण देने वालों को भी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है।जिसके कुछ समय बाद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी प्रक्रिया चल रही है। हमने नशा माफिया के खिलाफ विधानसभा में सख्त काननू बनाया है।नशे के व्यापारियों और संरक्षणकताओं पर भी कड़ा एक्शन होगा।उन्होंने नशे के खात्मे के लिए जनता से भी सहयोग की अपील की है। दोपहर बाद मौसम में आए बदलाव के कारण सीएम के चौपर को ऊना में ही रोकना पड़ा।जिसके चलते मुख्यमंत्री सडक मार्ग से ही शिमला के लिए रवाना हुए। बता दें कि सुक्खू सोमवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर हवाईयात्रा से पहुंचे थे। जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों उद्घाटन किए।लेकिन मौसम में आई करवट के बाद सीएम को बाई रोड़ वापिस जाना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश में चार दिन अंधड़-बिजली का अलर्ट, 20 जून से भारी वर्षा की चेतावनी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिली है। पिछले 24 घण्टों में बारिश होने से राज्य के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले कुछदिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके चलते मैदानी जिलों में लू से परेशान लोगों को और निजात मिलेगी। मौसम विभाग ने 20 जून से प्री-मानसून गतिविधियों की संभावना जताई है जबकि 25 जून के आसपास प्रदेश में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के प्रवेश करने का अनुमान है।

पिछले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान ऊना में 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 8.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कांगड़ा में 33.6 मिमी, करसोग में 27.0 मिमी, पालमपुर में 23.8 मिमी, धर्मशाला में 16.0 मिमी, जुब्बड़हट्टी में 12.0मिमी, कुफरी में 8.6 मिमी और शिमला में 7.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश से मौसम में थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश में तेज हवाओं का दौर भी जारी है। सबसे तेज हवा 59 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सिओबाग में चली, जबकि कुकुमसेरी में 43, बजौरा और नेरी में 41, कोटखाई में 39 और बिलासपुर में 37 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं।

मौसम विभाग के पूवार्नुमान के अनुसार 16 से 20 जून तक राज्य के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से अंधड़ चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। 16 और 17 जून को राज्य के कई भागों में तेज हवा और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 18 से 20 जून तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है। 21 और 22 जून को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यह बारिश खासकर मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिले जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा बीते कुछदिनों से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। दोपहर के समय तेज धूप और लू चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले दिनों कई स्थानों पर तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के अधिक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन आने वाले सप्ताह में मौसम के बदलने से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना बन रही है।

पांवटा साहिब में जो घटित हो रहा, वो दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक : भाजपा

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कांगड़ा-चंबा लोकसभा क्षेत्र भाजपा प्रभारी एवं विधायक विपिन सिंह परमार, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर तथा जिला पालमपुर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विनय शर्मा ने पांवटा साहिब में हाल ही में घटित मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी पर दर्ज एफआईआर पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पांवटा साहिब में जो कुछ भी हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर पीड़ित परिवार के प्रति अन्याय और एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त मामला बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में 50 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़ित परिवार और उनके सहयोगियों को प्रताड़ित कर रही है, जबकि दूसरी ओर आरोपी पक्ष और समुदाय विशेष का साथ दे रही है, वह सरासर गलत और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में ऐसी घटनाओं को कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी के परिवार और समर्थकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पीड़ित परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इसे भाजपा और प्रदेशवासियों का अपमान बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में उनकी सरकार द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 में जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा और जुमार्ने का प्रावधान है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन से उक्त मामले में निष्पक्ष और न्यायसंगत कार्रवाई की अपील की है, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने चेताया कि यदि पुलिस और प्रशासन इस तरह की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करते रहे, तो भाजपा इसे सड़क से सदन तक उठाएगी।

ढाई वर्षों के कार्यकाल में अब तक 5,500 शिक्षकों की नियुक्ति : हर्षवर्धन चौहान

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

शिशु विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल नाहन ने सोमवार को अपने 51वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि उद्योग, संसदीय कार्य तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान रहे। इस अवसर पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक, गुणात्मक, व्यावसायिक और संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है।

उन्होंने शिशु विद्या निकेतन स्कूल की सराहना करते हुए कहा कि यह विद्यालय एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान है, जहां से शिक्षा प्राप्त कर कई छात्र आज डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश व प्रदेश की सेवा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन हर बच्चे का स्वर्णिम काल होता है और यही समय है जब वे अपने भविष्य की नींव रखते हैं। उन्होंने बच्चों को लगन, मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई करने तथा शैक्षणिक और खेलकूद गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

मंत्री चौहान ने विद्यार्थियों को देश-विदेश की जानकारी के लिए समाचार पत्र पढ़ने और समाचार देखने की सलाह भी दी। साथ ही, उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे अपने माता-पिता और गुरुजनों की बातों को आदरपूर्वक सुनें और उनके मार्गदर्शन का पालन कर जीवन में आगे बढ़ें। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के की जा चुकी है तथा 15,000 और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

संक्षिप्त-समाचार

गलवान संघर्ष के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

लद्दाख। भारत-चीन सीमा पर गलवान घाटी में पांच साल पहले हुई झड़पों के दौरान बलिदान हुए सैनिकों को याद करते हुए भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक्स पर पोस्ट किया, ''गलवान दिवस पर फायर एंड फ्यूरी कोर ने हमारे बहादुरों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहे। गलवान घाटी में अदम्य साहस हर भारतीय के दिल में हमेशा गूंजता रहेगा। राष्ट्र उनके परिवारों का सम्मान करता है। उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

अक्षय लाबरू ने श्रीनगर के नए डीसी का पदभार संभाला

श्रीनगर। अक्षय लाबरू ने सोमवार को श्रीनगर जिले के नए डिप्टी कमिश्नर (डीसी) का पदभार संभाला। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अक्षय लाबरू ने जम्मू-कश्मीर में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएँ निभाईं और बडगाम के डिप्टी कमिश्नर भी रहे। डीसी श्रीनगर के रूप में उनकी नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश में शासन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक नियमित प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है। अधिकारियों ने नए डिप्टी कमिश्नर का स्वागत किया और प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया '

20 जून तक पूरे प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना

श्रीनगर। मौसम विभाग ने सोमवार को आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर में छिटपुट बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जून तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 21 से 23 जून के बीच मौसम में और अधिक सक्रियता की उम्मीद है जिससे जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में जम्मू क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस अवधि के दौरान जम्मू शहर में 46.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस बीच पूरे केंद्र शासित प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में तापमान औसत से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया जबकि जम्मू क्षेत्र में मौसमी मानक से 1-3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया। रात का तापमान भी असामान्य रूप से अधिक रहा। कश्मीर के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान औसत से 1-6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसी तरह जम्मू के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। कश्मीर में गुलमर्ग में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में बनिहाल में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

केंद्र ईरान में फंसे जम्मू-कश्मीर के छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है: भाजपा नेता

जम्मू। रैना ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने ईरान में फंसे जम्मू-कश्मीर के छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। जम्मू-कश्मीर भाजपा इकाई के पूर्व अध्यक्ष रैना ने कहा कि कई छात्रों और उनके अभिभावकों ने उनसे संपर्क किया है और वह उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और यदि आवश्यकता हुई तो उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि हम ईरान में पढ़ रहे अपने छात्रों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं।

उपराज्यपाल ने पास आउट पुलिस अधिकारियों से लोकाचार को बनाए रखने का आह्वान किया

एजेंसी (हि.स.)
उधमपुर

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को उधमपुर में प्रोबेशनर्स डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीवाईएसएसपी) 17वें बैच और प्रोबेशनर्स सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) 26वें बैच की पासिंग-आउट परेड में भाग लिया। कुल 49 पुलिस उपाधीक्षकों और 1112 प्रोबेशनरी सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) ने आज पुलिस अकादमी में अपना कठोर प्रशिक्षण पूरा किया।

अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने सभी पास आउट पुलिस अधिकारियों को बधाई दी और उनसे जम्मू-कश्मीर पुलिस के मूल्यों, परंपराओं और लोकाचार को बनाए रखने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने कहा कि हजारों वर्षों से हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग योद्धाओं का एक समूह अधर्म पर धर्म की जीत स्थापित करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देता रहा है। उन योद्धाओं में भगवान ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति, भगवान विष्णु की पालन-पोषण शक्ति और भगवान शिव की पूर्ण शक्ति है। परेड में वही अजेय शक्ति 49 प्रोबेशनर डीएसपी और 1112 प्रोबेशनर सब-इंस्पेक्टरों को प्रदान की जा रही है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस के उन बहादुरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे जम्मू-कश्मीर पुलिस के हमारे बहादुर कर्मियों और अधिकारियों पर गर्व है। पूरा देश हमारे पुलिस बल को पेशेवर क्षमता, कई मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने और आतंकवाद का बेरहमी से मुकाबला करने के लिए प्रशंसा और सम्मान के साथ देखता है। उपराज्यपाल ने कहा कि बहादुर कर्मियों को शांति, विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव तरीके से पूरे समाज की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे प्राचीन मूल्य सत्य, न्याय, नैतिकता, कानून और सुशासन पर केंद्रित हैं और इन मूल्यों को जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा समाज में संरक्षित और पोषित किए जाने की आवश्यकता है। उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर पुलिस बल से सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने, कट्टरपंथ को रोकने और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का पूर्ण उन्मूलन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के हमारे पराक्रमी योद्धाओं को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और खुफिया जानकारी, सामुदायिक जुड़ाव, प्रौद्योगिकी और अंतर-एजेंसी सहयोग की शक्ति का दोहन करना चाहिए।

पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले चार आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

सिरमौर जिले के माजरा थाना क्षेत्र में युवती के कथित अपहरण मामले ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी, तभी कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस टीम पर डंडों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार हमलावरों को हिरासत में लिया और सोमवार को उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि हमलावरों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एएसपी रोल्टा ने यह भी जानकारी दी कि कुछ लोगों ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 का उल्लंघन करते हुए संगठित रूप से माजरा थाने पर प्रदर्शन करने की कोशिश की। पुलिस ने इस घटनाक्रम को भी गंभीरता से लेते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

माजरा मामले में राजनैतिक षड्यंत्र के तहत हो रही कार्यवाई : डॉ राजीव बिंदल

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

सिरमौर जिला के माजरा क्षेत्र में युवती किडनैपिंग और उसके बाद हुई गिरफ्तारियों को लेकर सियासत गरमा गई है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने रविवार को नाहन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉ. बिंदल ने कहा कि माजरा में जो घटनाक्रम सामने आया है, वह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवती का अपहरण कर उसका गैरकानूनी रूप से धर्मांतरण किया गया है और इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के बजाय एक राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तारी की जा रही है।

उन्होंने कहा, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और जिन्हें नहीं किया गया है, यह सब एक सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है। ईंटों और हथियारों से हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि केवल हिन्दू समाज से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।

डॉ. बिंदल ने पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीण महिलाओं की पिटाई की गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि गैरकानूनी धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई की जाए। ईंटों से हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए ।महिलाओं की पिटाई के मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और युवती के अपहरण में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के उल्लंघन का मामला बनता ही नहीं क्योंकि विरोध प्रदर्शन उस क्षेत्र में हुआ था जो धारा 163 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर था।

शिमला में सेब सीजन की तैयारियां पूरी, पांच जगह नियंत्रण कक्ष स्थापित

ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

जिला शिमला में सेब सीजन की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सोमवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बचत भवन सभागार में इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेब के सफल और व्यवस्थित सीजन संचालन को लेकर तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की गई।

बैठक में सेब परिवहन, सड़क स्थिति, ट्रैफिक व्यवस्था, मजदूरों की उपलब्धता, पैकिंग सामग्री, नियंत्रण कक्षों की स्थापना तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बागवानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं।

सेब ढुलाई की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए जिले के पांच स्थानों–फागू, बलग, शोघी, गुम्मा और कुड्डु में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। मुख्य नियंत्रण कक्ष फागू में 15 जुलाई से कार्यशील होगा, जहां से पूरे जिले की निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम में टेलीफोन, फैक्स, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था के साथ कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। जरूरत अनुसार पुलिस बल भी विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेगा।

उपायुक्त ने कहा कि सेब सीजन के दौरान यदि किसी वाहन में ओवरलोडिंग पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए विशेष यातायात योजना बनाई गई है। ट्रकों को शिमला शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और उन्हें ढली-मेहली बाईपास से भेजा जाएगा। सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक सेब से लदे ट्राले ठियोग और शिमला के बीच नहीं चल सकेंगे।

उपायुक्त ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में सेब ढुलाई की दरें तय कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। दरों में सड़क की स्थिति, पेटियों की संख्या और डीजल कीमतों को ध्यान में रखा जाएगा। ये दरें नियंत्रण कक्षों, सार्वजनिक स्थलों और मंडियों में प्रदर्शित की जाएंगी। अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सेब कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आढ़तियों को उचित सत्यापन के बाद लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बिना लाइसेंस के आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही, चालकों और क्लीनरों को भी पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। पिकअप वाहनों के लिए शुल्क 200 रुपये, 6-पहिया ट्रकों के लिए 500 रुपये और ट्रालों के लिए 1000 रुपये तय किया गया है।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम, बागवानी उप निदेशक और एपीएमसी सचिव मंडियों का नियमित निरीक्षण करें। वहां स्वच्छता, पीने के पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

प्रशासन को इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पैदावार की उम्मीद है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

नवोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

नायब सैनी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की निविदा राशि वाली प्रमुख सिंचाई और जल संसाधन परियोजनाओं की समीक्षा की

इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ाना, सिंचाई दक्षता में सुधार करना

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार सिंचाई एवं जल ढांचे को मजबूत करने के लिए दृढ़ एव ठोस कदम उठा रही है, जिसके तहत सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पांच प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जिनमें से प्रत्येक में 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ाना, सिंचाई दक्षता में सुधार करना शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज यहां सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं की इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग के अनुमोदन में देरी के चलते परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। उन्होंने ड्राइंग में अनुमोदन में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने परियोजनाओं में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि दादूपुर से हमीदा हेड तक नई समानांतर लाइन चैनल (पीएलसी) और डब्ल्यूजेसी का आधुनिकीकरण 274.87 करोड़ रुपये के साथ किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य गैर-मानसून अवधि के दौरान हथिनीकुंड बैराज से होने वाले रिसाव के नुकसान को कम करना है। अब तक 64.5 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। परियोजना को मार्च, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डब्ल्यूजेसी ब्रांच (75.25 किमी) तक ऑग्मेंटेशन नहर का पुनर्निर्माण 383 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना का 81 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और जून, 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इसी प्रकार पीडी ब्रांच (मुनक से खुबडु हेड) की लाइनिंग और रीमॉडलिंग का कार्य 197.80 करोड़ रुपए से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 145.25 किलोमीटर में कंक्रीट लाइनिंग का कार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि 145.99 करोड़ रुपये की लागत वाली हथिनीकुंड बैराज के डाउनस्ट्रीम में डायाफ्राम वॉल के निर्माण की संरचनात्मक सुरक्षा परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (एनपीसीआईएल) के तहत गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पानी की आपूर्ति के लिए 442.64 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बैरल और लिंक चैनल का निर्माण किया जा रहा है। इसका अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मानसून 2025 के लिए सिंचाई विभाग ने मानसून के दौरान निर्बाध जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की है। इसमें हथिनीकुंड बैराज पर अस्थायी सुरक्षात्मक कार्य और महत्वपूर्ण नहरों में निर्वहन क्षमता को अधिकतम करना शामिल है। हरियाणा सरकार इन मेगा-प्रोजेक्ट्स के समय पर क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य की जल सुरक्षा और कृषि स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। चुनौतियों पर काबू पाने और तेजी से काम पूरा करने के लिए निरंतर निगरानी, अंतर-विभागीय समन्वय और हितधारक जुड़ाव को प्राथमिकता दी जा रही है।

अपराधियों के सामने घुटने टेकती दिख रही है प्रदेश की भाजपा सरकार: कुमारी सैलजा

संवाददाता
चंडीगढ़

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लोग दहशत में है, हर वर्ग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है, गैंगस्टर सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला रहे है, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए है। हालात ये है कि 12 जिलों में 300 शराब की बोली गैंगस्टर्स की धमकी के चलते नहीं हो पा रही है, धमकी के चलते कोई भी शराब कारोबारी बोली लगाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। दूसरी ओर बढ़ते अपराध की जड़ में नशा एक प्रमुख कारण है जिसे खत्म करने दिशा में केवल सरकार बयानबाजी तक सीमित है, गली गली में नशा बिक रहा है जिससे साफ लगता है कि प्रदेश की पुलिस कितनी चौकस है। मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज दिखाई नहीं आ रही है अगर जिला में अपराधियों का बोलबाला है, किसी न किसी जिला में हर रोज हत्याएं हो रही है, लूटपाट और छीना झपटी आम हो गई है, गैंगस्टर्स के आगे पुलिस बौनी नजर आ रही है, गैंगस्टर्स सरेआम वारदात को अंजाम देकर निकल जाते है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रह जाती है। शराब कारोबार पर गैंगस्टर्स नजरें लगाए हुए है, ठेकों की बोली को लेकर गैंगस्टर्स आमने सामने है, ठेका पर सरेआम फायरिंग कर और धमकी भरी पर्ची छोड़कर दहशत फैलाई जा रही है। हालात ऐसे है कि नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश के 12 जिलों में 300 शराब ठेकों की बोली होनी है, हालात ऐसे है कि धमकी के चलते कोई भी शराब कारोबारी बोली लगाने के लिए आगे नहीं हो रहा है, अभी तक इन ठेकों की बोली नहीं हो पाई है। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि शराब कारोबारी इस मामले में मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी मिल चुके है उन्हें सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया हुआ है पर शायद शराब कारोबारियों को सरकार के इन आश्वासनों पर विश्वास ही नही है जिसके चलते इन 300 शराब ठेकों की बोली नहीं हो पा रही है। गैंगस्टर्स की धमकी के चलते सरकार शराब के ठेकों की बोली कराने में नाकाम रही है इससे से यही लग रहा है कि सरकार पर गैंगस्टर्स हावी है, अगर सरकार की ऐसी हालात है तो प्रदेश में आम व्यक्ति की हालात क्या होगी। रोहतक, महम, हिसार में शराब ठेकों पर गैंगस्टर्स ने फायरिंग कर दहशत की ऐसी पथकथा लिख दी है कि शराब ठेकों की बोली अधर में ही रह जाएगी। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में अपराध की जड़ नशा है, सरकार नशा रोकने की दिशा में सख्त कदम नहीं उठा रहर है, नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है नशीले पदार्थ भी बरामद किए जा रहे है फिर भी नशा गली गली बिकना सरकार की विफलता को दशार्ता है। हर जिला में पुलिस कर्मी केवल चालान काटकर जनता को परेशान करने में लगे हुए है जबकि अपराधी सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

ऐलिश सैनी का नीट यूजी 2025 में सफलता पर किया स्वागत

संवाददाता
लाडवा

साधारण परिवार से संबंध रखने वाले ऐलिश सैनी ने नीट यूजी -2025 ने अखिल भारतीय स्तर पर 1194 तथा केटेगरी में 368 रैंक प्राप्त कर न केवल संजय गाँधी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल धनोरा-लाडवा बल्कि अपने माता पिता और क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रधान पवन गर्ग ने ऐलिश सैनी और उसके अभिभावकों को उसकी असाधारण सफलता पर बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की `विद्यालय की प्रबंधन समिति की ओर से विद्यालय के सचिव रविंद्र बंसल, विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा और अध्यापकों ने ऐलिश सैनी और उसकी दादी उषा देवी का विद्यालय प्रांगण में फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और बधाई दी। उल्लेखनीय है कि बहलोलपुर निवासी ऐलिश सैनी के पिता जसविंदर सिंह हरियाणा राज्य परिवहन विभाग में कंडक्टर के पद पर कार्यरत हैं तथा माता एक गृहिणी है । ऐलिश सैनी ने कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक संजय गाँधी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की` उसने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय, शिक्षकों, अभिभावकों और ईश्वर को दियो उसने विद्यालय प्रबंधन समिति एवं स्टाफ का विशेष तौर पर धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लाडवा विधानसभा के 40 गांवों की युवतियां सिलाई सीखकर बनेंगी आत्मनिर्भर : कैलाश सैनी

अनिल गोयल
लाडवा

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विधानसभा लाडवा के 40 गांवों की युवतियों को सिलाई सीखकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के योजना के तहत सरकार अंत्योदय परिवारों को स्वरोजगार और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाने के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपना रही है। इनमें से सिलाई केन्द्र खोलना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चारों मंडलों में एक-एक ब्यूटीशियन सेंटर, सोलर रिपेयर केन्द्र भी खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी सोमवार को स्कील फाउंडेशन गुरुग्राम के सहयोग से गांव बिहोली, रामसरण माजरा, बकाली और बपदी में तैयार किए गए सिलाई सेंटरों का उद्घाटन किया। उनके साथ स्कील फाउंडेशन गुरुग्राम के एजीएम आरके सिंह भी मौजूद रहे। प्रत्येक गांव में एक ग्रुप में 50-50 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाडवा विधानसभा के सभी मंडलों में एक-एक सिलाई सेंटर की शुरूआत की गई है। इन केंद्रों पर अंत्योदय की नीति से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक सिलाई सेंटर पर आस-पास के 10-10 गांवों को कवर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार की अंत्योदय नीति का उद्देश्य प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों की आय बढ़ाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। अंत्योदय परिवारों को स्वयं का रोजगार खोलने और पहले से चल रहे रोजगार में विकास करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परिवार पहचान पत्र के तहत पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी ने कहा कि अंत्योदय की योजना के तहत सरकार छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। इस मौके पर स्कील फाउंडेशन गुरुग्राम के एजीएम आरके सिंह, मंडल अध्यक्ष शिव गुप्ता, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, सुनील, ओम प्रकाश, कौशल सेन, भीम बेडथला, शिव राम, अनिल टाटकी, रिंकू कश्यप, डिम्पल सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

संक्षिप्त-समाचार

हरियाणा में हुए पंचायत उपचुनाव में 73.25 प्रतिशत रहा मतदान

चंडीगढ़। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा है कि कल 15 जून को पंचायतों के उपचुनाव व कुछ पंचायतें जो नगरपालिका से पुनः पंचायत बनी हैं के आम चुनाव को सम्पन्न करवाने उपरांत अब राज्य चुनाव आयोग के पास किसी भी पंचायत का चुनाव लंबित नहीं है। इसके अलावा, कालांवाली, सिरसा के लिए आम चुनाव के लिए मतदान 29 जून, 2025 को होना है। उसके लिए आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। मतदान गणना 30 जून को होगी इसके साथ ही किसी भी स्थानीय निकाय के लिए होने वाले चुनाव आयोग के पास लंबित नहीं है। कालांवाली नगरपालिका में 17 वार्डों के लिए चुनाव होना है। धनपत सिंह आज 15 जून को हुए पंचायतों के हुए उपचुनाव के बाद अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव का प्रतिशत गर्मी के बावजूद भी 73.25 प्रतिशत रहा जो दशार्ता है कि लोगों की पंचायती चुनाव में काफी दिलचस्पी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट स्टे को छोड़कर किन्हीं कारणों से जैसा कि चयनित जन प्रतिनिधि द्वारा स्वेच्छा से त्याग पत्र देना, मृत्यु हो जाना या किसी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सीट रिक्त हो जाती है तो उस स्थिति में आयोग को 6 महीने के अंदर-अंदर पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। धनपत सिंह ने बताया कि कुल मिलाकर पंचायत स्तर पर पंचों की 830, सरपंचों की 74, पंचायत समिति सदस्यों की 17 और जिला परिषद सदस्य की 1 सीट के लिए उपचुनाव निर्धारित किए गए थे। इनमें से पंचों व सरपंचों के पदों पर कई उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। उन्होंने बताया कि अब चरखी दादरी जिले की बाढ़डा खंड की ग्राम पंचायत हंसावास खुर्द तथा बाढ़डा व झज्जर जिले के बादली खंड की ग्राम पंचायत बादली व मुहम्मदपुरा माजरा तथा फैजाबाद ग्राम पचांयतों के पंचों व सरपंचों के आमचुनाव के साथ-साथ 56 पंचों, 61 सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों के 8 सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्य की 1 सीट के लिए चुनाव 15 जून को सुबह 8 बजे सांय 6 बजे तक करवाए गए। मतदान में ईवीएम का प्रयोग किया गया।

बिना नंबर प्लेट व पटाखा बुलेट के लिए लाडवा पुलिस ने चलाया अभियान

लाडवा। लाडवा थाना प्रभारी सुनील वत्स ने लाडवा में एक विशेष अभियान चलाकर लाडवा शहर में बिना नंबर प्लेट व पटाखा बुलेट मोटरसाइकिल चालकों को व काले रंग की गाड़ियों वाले वाहन चालकों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुनील वत्स ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के आदेश अनुसार लाडवा सीएम सिटी होने के कारण यहां पर पुलिस द्वारा कुछ नियमों के अंतर्गत वाहन चालकों की तलाशी की जा रही है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना होने से रोका जा सके। उन्होंने बताया पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान बिना नंबर प्लेट, बिना कागजात और काले रंग की फिल्म चढ़ी कारों पर कार्रवाई अमल में जा रही है। सुनील वत्स ने कहा लाडवा की जनता का यह कर्तव्य बनता है कि वह पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में हमारा सहयोग करें। सुनील वत्स ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वह बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलाएं।

ओ आर एस का घोल पिलाएं, बच्चों को दस्त से बचाएं

संवाददाता
लाडवा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ कृष्णकांत ने दस्त रोको अभियान की शुरूआत करते हुए सभी को बताया कि 16 जून से 31 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा ।5 साल तक के बच्चों में 40% मृत्यु दस्त के कारण हो जाती हैं । जोकि एक गंभीर विषय है ।इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर ये प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि बच्चों की दस्त के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सके ।सभी आशा वर्कर्स को बताया गया कि वे घर घर जाकर 5 साल तक के सभी बच्चों के लिए ओ आर एस के पैकेट और जिंक की गोलियां दें । घर में ओ आर एस का घोल तैयार करने की विधि बताई गई । 2 महीने से 6 महीने के बच्चे को जिंक की आधी गोली ओर 6 महीने से 5 साल के बच्चे को 1 गोली 14 दिन के लिए देनी है ।ताकि बच्चे को दस्त जैसी जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके ।

गर्मी के मौसम में सावधानियां रखने से बचा जा सकता है गंभीर बीमारियों से : डॉक्टर

दस्त के कारण बच्चों में पानी की कमी हो जाती है ।इसलिए बच्चों को निर्जलीकरण से बचाने के लिए ओ आर एस का घोल बनाकर हर दस्त के बाद बच्चे को पिलाना चाहिए । ओ आर एस के पैकेट और जिंक की गोलियां हर स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं ।घर में भी ये तैयार किया जा सकता है ।इस से बच्चों को पानी की कमी होने से बचाया जा सकता है । वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्णकांत जी ने बताया कि अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोना चाहिए ।शौच के बाद व खाना खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोने चाहिए ।सभी खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए ताकि वे दूषित ना हों ।पीने के लिए साफ पानी का उपयोग करें ।वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्णकांत जी ने बताया कि इस प्रोग्राम को सफल बनाकर हम दस्त के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम कर सकते हैं ।

आज से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का दिया जाएगा

संवाददाता
लाडवा

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में लाडवा के शिवाला रामकुण्डी में 18 और 19 जून को सुबह 5 से 7 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक विशाल योगा कैंप का आयोजन किया जाएगा ,सुबह 5:00 बजे से 7:00 बजे तक जिसमे लाडवा की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं और लाडवा के आसपास से सभी योग प्रेमी,योग साधक इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे और पूरे लाडवा शहर योगमय किया जायेगा यह जानकारी पतंजलि के योग आचार्य कमल किशोर जी ने दी, इस योग शिविर में पतंजलि योगपीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश मित्तल जी, हरिद्वार से पधारे साधु महात्माओं, स्वामी प्रज्ञान देव जी, स्वामी विश्व देव जी, स्वामी आदि देव जी, स्वामी सुखदेव जी, स्वामी वन देव जी, स्वामी परसन देव जी,और, स्वामी भव देव जी,का आशीर्वाद प्राप्त होगा और लाडवा वासिओ को योग,आयुर्वेद,एक्यूप्रेशर का गहरा ज्ञान सीखने का मौका मिलेगा जिसमें सभी को विशेष आसन प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करवाया जायेगा,,, इसके साथ-साथ ही उन्होंने बताया कि इस योग दिवस के प्रचार प्रसार में लाडवा के सभी 55 गांव में घर-घर जाकर योग दिवस का निमंत्रण सभी को दिए जा चुका है और इसी के साथ ही अब लाडवा शहर जो मान्य मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वार्ड में घर में जा जाकर योग का संदेश दिया जा रहा है, जिसमें आज लाडवा के 6 वार्डों में घर-घर जाकर योग का प्रचार किया गया । और पतंजलि योग समिति से डॉक्टर मुकेश जी ने को बताया कि योग दिवस पर इस विश्व कीर्तिमान के साक्षी सभी बने और इस विशाल शिबिर में आप सभी परिवार सहित सभी जरूर पहुंचे, उन्होंने बताया के आचार्य विकास जी, बालकृष्णन मल्होत्रा जी,ओम प्रकाश मल्होत्रा जी,, उत्तर प्रदेश के प्रभारी विपिन जी , जींद के कार्यकर्ता, सिरसा के कार्यकरता, हिसार के कार्यकर्ता, यमुनानगर के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर सभी को योग का संदेश दे रहे हैं।

स्वास्थ्य

आभा आईडी से लोगों को मिल रही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राज्य में 1.63 करोड़ आभा कार्ड बनाए गए

संवाददाता
चंडीगढ़

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने आज अपना और अपने स्टाफ का आभा कार्ड बनवाया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य एक सहज और अंतर संचालन (इंटरऑपरेबल) योग्य डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को डिजिटल बनाना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और अंतर-संचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों का उपयोग करके विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध डेटा साझाकरण को सक्षम बनाना है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ उठाना है। यह योजना कड़े डेटा सुरक्षा उपायों के साथ बनाई गई है। रोगी का डेटा केवल स्पष्ट सहमति से साझा किया जाता है। स्वास्थ्य डेटा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास रहता है; एबीडीएम संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा को केंद्रीकृत रूप में संग्रहीत करने के बजाय सुरक्षित आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। कुछ डेटा (आभा, एचपीआर, एचएफआर) को अंतर संचालनीयता और विश्वास के लिए केंद्रीय रूप से संग्रहीत किया जाता है। मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अपनी आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) आईडी से लिंक कर सकता है। वह अपनी सहमति से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहीत, एक्सेस और साझा कर सकता है। हरियाणा में संचालन के लिए एबीडीएम टीम जागरूकता पैदा करने और आभा आईडी बनाने की सुविधा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राज्य मिशन निदेशक श्रीमती संगीता तेतरवाल के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस अवसर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) श्री कैलाश सोनी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आभा कार्ड बनाने के लाभ बताए और इस मिशन के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भिन्न होने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक 1.63 करोड़ से अधिक आभा कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीएचसी मुलाना को आभा कार्ड धारकों के लिए प्रदेश का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है, जो पूरी तरह कार्यात्मक है। यहां मरीज ऑनलाइन पंजीकरण कराकर इलाज करा सकते हैं। सीएचसी मुलाना में मरीजों को पंजीकरण के लिए लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही यह योजना राज्य के सभी 22 जिलों में प्रति स्वास्थ्य संस्थान 2 स्वास्थ्य केंद्रों यानि कुल 44 स्वास्थ्य संस्थानों में लागू की जाएगी। स्वास्थ्य संस्थानों के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में यह एक नई और परिवर्तनकारी पहल साबित होगी।

11 साल में टोल फ्री नंबर पर मिली सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान: राजेश नागर

संवाददाता
चंडीगढ़

2014 से लेकर फरवरी 2025 तक उपभोक्ता सहायता केंद्र में प्राप्त हुई 76,826 शिकायतें, सभी का किया गया समाधान : राजेश नागर

हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है कि विभाग ने पिछले 11 सालों में प्रदेश के उपभोक्ता सहायता केंद्र में आई सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान कर दिया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र में हेल्पलाइन नंबर पर वर्ष 2014 से फरवरी 2025 तक कुल 76,826 शिकायतें प्राप्त हुई तथा सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र तत्परता से प्रदेश के आम जन की समस्याओं के समाधान में जुटा हुआ है।

विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण और समाधान करने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत हैं। विभाग द्वारा हरियाणा राज्य में उपभोक्ता शिकायतें सुलझाने के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन संचालित है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर है : 1800-180-2087, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नंबर है: 1967, एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड के लिए नंबर है: 1800-180-2045 और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रवासी मजदूर के लिए टोल फ्री नंबर: 14445 है।

संपादकीय

सबूत का दुरुपयोग: जब भारतीय नागरिकों को पुलिस ने बताया बांग्लादेशी

इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में नागरिकता केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी पहचान है। लेकिन जब इसी पहचान को संदेह के दायरे में लाकर निर्दोष नागरिकों को विदेशी करार दे दिया जाए और उन्हें उनके ही देश से जबरन बाहर कर दिया जाए, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर गहरी चोट है। 16 जून 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में एक 65 वर्षीय महिला को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर इस संवेदनशील मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में ला दिया है। आइये समझते हैं भारत में नागरिकता संकट की जड़ों के बारे में। असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में वर्षों से यह समस्या उभर रही है, जहाँ नागरिकता का सबूत होने के बावजूद हजारों लोग अवैध प्रवासी घोषित कर दिए जाते हैं। हाल के वर्षों में एन आर सी की प्रक्रिया और सी ए ए के क्रियान्वयन ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। नागरिकों को अक्सर तब तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जब तक वे अपने भारतीय होने का प्रमाण अदालतों में नहीं दे पाते – और कई बार तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब बात करते हैं असली नागरिकों और झूठे ठप्पे की। 2024-2025 के दौरान दर्जनों ऐसे मामले सामने आए जहाँ पुलिस ने भारतीय दस्तावेजों को नकारते हुए नागरिकों को बांग्लादेशी घोषित किया। नदिया, मुर्शिदाबाद, बारपेटा और बोंगईगांव जैसे ज़िलों में स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। जून 2024 में असम के बारपेटा ज़िले से एक वायरल वीडियो सामने आया था, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति – अब्दुल हमीद – रोते हुए बता रहा था कि वह 1960 से उस गांव में रह रहा है, लेकिन पुलिस ने एन आर सी में नाम न होने के आधार पर उसे विदेशी घोषित कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया। पुलिस की मर्जी को लेकर उठते सवालों की बात करें तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इन नागरिकता विवादों में यह अधिकार बार-बार कुचला गया है। 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' जैसी संस्थाएं, जो विदेशी नागरिकों की पहचान तय करती हैं, अक्सर पुलिस रिपोर्टों को ही अंतिम साक्ष्य मान लेती हैं।मानवाधिकार आयोग और नागरिक संगठनों ने बार-बार चेताया है कि इन ट्रिब्यूनलों में पारदर्शिता और न्यायिक क्षमता की भारी कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि ह्लकिसी की नागरिकता तय करना सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह न्यायिक विवेक का मामला है।ह्व एन आर सी , सी ए ए और उनका दुरुपयोग भी किसी से छिपा नहीं है। 2019 में असम में जब एन आर सी की अंतिम सूची जारी हुई, तब लगभग 19 लाख लोग बाहर रह गए। इनमें न केवल मुस्लिम समुदाय, बल्कि सैकड़ों हिंदू, आदिवासी और गरीब भी थे। सी ए ए के तहत जहां कुछ समुदायों को नागरिकता का संरक्षण मिला, वहीं एन आर सी से बाहर लोगों को अवैध मानकर कार्रवाई जारी रही। पुलिस के लिए यह 'सूची से बाहर = विदेशी' की नीति बन गई, जिसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुआ। 2025 में सी ए ए को लेकर जारी केंद्र सरकार की समीक्षा प्रक्रिया भी धीमी रही, जिससे हजारों प्रभावित लोग अनिश्चितता में जी रहे हैं। यह भी सच है कि राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नागरिकता के इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। सत्ताधारी दलों पर आरोप है कि वे वोट बैंक की राजनीति के लिए खास समुदायों को निशाना बना रहे हैं। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे गरीब मुस्लिम, दलित और बंगाली भाषी नागरिक, जिनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है। बांग्लादेश पहले से ही स्पष्ट असहमति जता चुका है। बांग्लादेश सरकार ने कई बार भारत को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं मानेगी जिसके पास बांग्लादेशी नागरिक होने का प्रमाण न हो। वर्ष 2024 के अंत में ऐसे 117 निर्वासितों को ढाका प्रशासन ने भारत वापस लौटा दिया क्योंकि उनके पास कोई वैध पहचान नहीं थी। यह भारत के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी भी है।जब किसी को विदेशी घोषित किया जाता है, तो उसका केवल अधिकार नहीं, पूरा जीवन संकट में आ जाता है। डिटेंशन सेंटर में महीनों या वर्षों की कैद, परिवार से अलगाव, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक पीड़ा झ्र ये सारी सजा उस व्यक्ति को भुगतनी पड़ती है जो अपने देश का ही नागरिक है।एक महिला, शारमीन खातून, जिसे 2023 में बांग्लादेशी बताकर जेल भेजा गया था, 2025 में हाईकोर्ट से बरी हुई – लेकिन वह अपने पति को खो चुकी थी, बेटा स्कूल से बाहर हो चुका था और वह मानसिक आघात से जूझ रही थी। कानूनी स्थिति और सुधार की आवश्यकता बिलकुल जरूरी है। भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 साफ करता है कि नागरिकता के निर्धारण के लिए जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिककरण जैसे चार वैध मार्ग हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार स्पष्ट कर चुका है कि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले व्यापक, निष्पक्ष और न्यायिक जांच अनिवार्य है। सुधारों से संबंध में कई प्रस्ताव हैं। जैसे पुलिस पर निगरानी बढ़ेः स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा नागरिकता जांच में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो। ट्रिब्यूनल सुधारः न्यायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए और पुलिस रिपोर्ट के स्थान पर निष्पक्ष दस्तावेजी जांच को महत्व मिले। फ्री लीगल एडः आर्थिक रूप से कमजोर तबके को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। एन एच आर सी और मीडिया निगरानीः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान ले और मीडिया ऐसे मामलों को जोर से उजागर करे। अंत में कह सकते हैं कि जब हम 'आजाद भारत' में रह रहे हैं, तब किसी भारतीय को नागरिकता के लिए सबूत देना पड़े, वह भी पुलिसिया जुल्म के साये में – तो यह केवल संवैधानिक संकट नहीं, बल्कि नैतिक विफलता भी है। सरकार को चाहिए कि वह तुरंत प्रभाव से डिटेंशन सेंटरों की समीक्षा करे, बांग्लादेश भेजे गए निदोषों को वापस लाए और नागरिकता निर्धारण को पारदर्शी और मानवीय बनाए। एक लोकतंत्र वही होता है जो अपने सबसे कमजोर नागरिक की भी सुन सके – वरना इतिहास उसे क्षमा नहीं करता।

आज का राशिफल

मेषः आज का दिन ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। बच्चों के लिए कोई उपहार खरीद सकते हैं। निवेश के लिहाज से शेयर मार्केट में कदम रखना लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

वृषभः व्यवसाय से जुड़ी बाधाएं दूर होने के संकेत हैं। आप अपनी जीवनशैली में बदलाव लाकर दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय प्रेरणा लें। विरोधियों की चालें असफल होंगी। अधूरे काम पूरे करने का अवसर मिलेगा, जिससे आत्मसंतोष का अनुभव होगा।

मिथुनः कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप शांत रहकर स्थिति को संभाल लेंगे। धार्मिक कार्यों और ध्यान में रुचि बढ़ेगी। पिता की सेहत को लेकर सतर्क रहें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है। वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा, लेकिन सरकारी कामों में विलंब हो सकता है।

कर्कः बीते अनुभव आज फायदेमंद साबित होंगे। हालांकि, कार्यालय में उच्चाधिकारी आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं। बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। खानपान में लापरवाही से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। थकावट और शरीर में अकड़न की शिकायत रह सकती है।

सिंहः दाम्पत्य जीवन में प्रेम और भरोसा गहरा होगा। व्यापार में विस्तार के संकेत हैं। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। परिवार में भावुक माहौल बना रहेगा। लंबित कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे राहत महसूस होगी।

कन्याः कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। लेकिन दूसरों के निजी मामलों से दूरी बनाए रखें। व्यापार में साझेदारों से मतभेद हो सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। कुछ काम समय पर पूरे नहीं होंगे, फिर भी आप सूझबूझ से स्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे।

तुलाः पदोन्नति के योग हैं। पुराने मित्रों से संबंध मजबूत होंगे। बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज न करें। पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों में तनाव की आशंका है। आलोचना झेलनी पड़ सकती है, इसलिए संयम बरतें।

वृश्चिकः सुबह सुस्ती भरी हो सकती है। घुटनों का दर्द परेशान करेगा। कार्यनीति में बार-बार बदलाव नुकसानदायक हो सकता है। कार्यों को अधूरा न छोड़ें। कानूनी मामले आपके पक्ष में रह सकते हैं। निजी नौकरी में आय बढ़ने की संभावना है।

धनुः कार्यक्षेत्र में महत्त्वपूर्ण बैठक में शामिल हो सकते हैं। जीवनसाथी से संबंध और मधुर होंगे। परिवार के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है, जो मन को सुकून देगा। खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए दिन अनुकूल है।

मकरः आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर रह सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। प्रेम संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। नए लोगों से अधिक मेलजोल नुकसानदायक हो सकता है।

कुंभः कार्यक्षेत्र में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। व्यापार में बड़ा मुनाफा संभव है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए अनुबंध के अवसर हैं। करियर से जुड़ी उलझनें खत्म होंगी। रिलेशनशिप को लेकर दबाव महसूस कर सकते हैं।

मीनः आज आपका स्वभाव सहकर्मियों को खल सकता है। शत्रु नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। विदेशी कंपनियों में काम करने वालों को पदोन्नति मिल सकती है। पैरदर्द और मांसपेशियों की समस्या रहेगी। कृषि कार्यों में हानि हो सकती है। अपेक्षाएं सीमित रखें।

पवन ऊर्जा क्षेत्र और तीन प्रमुख चुनौतियां

मुकुंद (हि.स .)

देश में बिना बाधा के बिजली आपूर्ति में पवन ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इस दिशा में मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से प्रयासरत है। सरकार मानती है कि इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। इनसे पार पाने के बाद ही स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊजामंत्री प्रह्लाद जोशी ने 15 जून को बेंगलुरु में वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए तीन चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले, हमें 24 घंटे बिजली और ग्रिड स्थिरता प्रदान करने के लिए पवन को सौर और भंडारण (बीईएसएस) के साथ जोड़ना होगा। दूसरा, शुल्क प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। 3.90 रुपये प्रति यूनिट की दर बहुत अधिक है। हमें लागत कम करने के लिए मिलकर काम करना होगा। तीसरा, घरेलू विनिर्माण को और अधिक कुशल बनना होगा। साथ ही अपने लक्ष्यों को पूरा करने के साथ निर्यात को प्रोत्साहन भी देना होगा।

वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस पर आयोजित सम्मेलन के संदर्भ में भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार के निरंतर नीतिगत समर्थन से पवन ऊर्जा क्षेत्र ने पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के प्राधिकरणों, डिस्कॉम, सीपीएसयू, पवन उद्योग, शिक्षाविदों, प्रमुख विचारकों, प्रमुख हितधारकों आदि की भागीदारी से देश में पवन ऊर्जा विकास की प्रगति सहित प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम में पवन स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ (डब्ल्यूआईपीपीए), भारतीय पवन टरबाइन निमार्ता संघ (आईडब्ल्यूटीएमए) और भारतीय पवन ऊर्जा संघ (आईडब्ल्यूपीए) का भी सहयोग रहा। केंद्रीयमंत्री जोशी ने कार्यक्रम में मौजूद हितधारकों को संबोधित किया। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत की रणनीति के केंद्र में है। जोशी ने कहा कि वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए भारत को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है, चाहे वह सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो या ऊर्जा का कोई अन्य स्वरूप हो।

कार्यक्रम में जोशी ने यह कहकर चिंता कम की कि भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य महत्वाकांक्षी और स्पष्ट हैं। वर्ष 2030 तक हमारी बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों से होगा। वर्ष 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के में पवन ऊर्जा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा रणनीति का घटक नहीं है, लेकिन यह इसके दिल में है और आत्मनिर्भर भारत के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमें 'विनिर्माण के लिए अक्षय ऊर्जा और घरेलू खपत के लिए पारंपरिक ऊर्जा' का एक दृष्टिकोण दिया है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अक्षय ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और उपयोग के महत्व पर बल देता है, ताकि जब भारत निकट भविष्य में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाए, तो वह अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में सक्षम हो सके।

जोशी ने कहा कि भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इसकी विश्व स्तर पर चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता है और यह तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक है। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 10 वर्ष में अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है। सरकार इस क्षेत्र को पूरी गंभीरता से सहायता प्रदान कर रही है। इस वर्ष अक्षय ऊर्जा बजट में 53 प्रतिशत यानी 26,549 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा पवन ऊर्जा को दिया गया है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग की ओर संक्रमण अपरिहार्य है। राज्यों को इस संक्रमण का नेतृत्व करना चाहिए। भूमि की उपलब्धता और पारेषण में देरी को दूर करना होगा। यह संकोच का समय नहीं है, यह कार्यान्वयन का समय है।

उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत 225 किलोवाट से लेकर 5.2 मेगावाट तक की क्षमता वाले पवन टर्बाइनों का निर्माण कर रहा है। इसमें 14 कंपनियां 33 मॉडल तैयार कर रही हैं। यह टर्बाइन हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और वैश्विक स्तर पर लागत-प्रतिस्पर्धी भी हैं। जोशी का मानना है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए समन्वित राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता होगी। इसलिए हम पांच प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

इसके तहत मध्य प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे नए राज्यों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात और तमिलनाडु में चार गीगावाट के लीजिंग क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। भंडारण से जुड़े व्यावसायिक मॉडलों के माध्यम से चौबीसों घंटे चलने वाली और दृढ़ हरित ऊर्जा रणनीतियों में पवन ऊर्जा को एकीकृत किया जाएगा। ग्रिड का आधुनिकीकरण किया जाएगा। परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित पूवार्नुमान में निवेश किया जाएगा। पूरी पवन ऊर्जा मूल्य शृंखला में स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन समय की जरूरत है। जोशी ने कार्यक्रम में पवन ऊर्जा रूपरेखा और विनिर्माण कार्ययोजना पर रिपोर्ट भी जारी की। इस रिपोर्ट में मजबूत और आत्मनिर्भर पवन ऊर्जा इको सिस्टम पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने सुखद यह है कि कर्नाटक 1331.48 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु (1136.37 मेगावाट) और गुजरात (954.76 मेगावाट) का स्थान है।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

चारधाम यात्रा में मौत के उड़नखटोले !

एडवोकेट डॉ श्रीगोपाल नारसन (हि.स.)

उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 15 जून को तड़के एक हेलीकॉप्टर (उड़नखटोला) फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिनमें एक 2 वर्ष का बच्चा भी था। इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई है। खराब मौसम के कारण यह हादसा गौरीकुंड और त्रिजुगीनारायण के मध्य गौरीकुंड के जंगलों के ऊपर हुआ। सुबह लगभग साढ़े पांच बजे हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी और अचानक यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खराब मौसम के कारण दृश्यता कम होने की वजह से इस हादसे का होना माना जा रहा है। तत्काल राहत और बचाव दल भेजे गए। रास्ते में मौसम खराब होने के कारण अन्य स्थान पर हार्ड लैंडिंग करने से हेलीकाप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है। इसी जून के पहले सप्ताह में भी एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण उसकी बीच सड़क पर इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा था। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम यात्रियों को लेकर जा रहा था। हेलीकॉप्टर में पांच यात्री, पायलट और सह-पायलट सवार थे।

इस दौरान सह-पायलट को मामूली चोटें आई थीं। यह हेलिकॉप्टर बड़ासु हेलीपैड से उड़ान भरने के तुरंत बाद आपातकालीन लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ था। इस साल मई में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से छह सप्ताह में यह पांचवां हेलिकॉप्टर हादसा है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवा से केदारनाथ धाम में यात्रा करने वालों की संख्या हर साल लगभग 90 हजार से एक लाख श्रद्धालुओं की है। प्रतिदिन लगभग 1500 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मौजूदा समय में हेलीकॉप्टर की उड़ान कम होने और कुछ एजेंसियों को सस्पेंड किए जाने के बाद टिकट रद्द भी किए जा रहे हैं। टिकट रद्द के बाद श्रद्धालुओं को उनके पैसे वापस करने होंगे। अपनी व्यवस्थाओं से चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर मायूसी है।

उत्तराखंड सरकार ने 15 जून के इस हादसे के बाद उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव इन दुर्घटनाओं को लेकर बैठक भी कर रहे है। उत्तराखंड में 7 जून को 253 हेलीकॉप्टर शटल सेवा चली, जिसमें 1404 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ तक का सफर तय किया। 8 जून को 208 हेलीकॉप्टर शटल सेवा चली, जिसमें 1161 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ तक का सफर तय किया। 9 जून को हेलीकॉप्टर 186 शटल सेवा चली जिसमें 1043 भक्तों ने बैठकर केदारनाथ के दर्शन किए। 10 जून को मात्र 143 उड़ान केदारनाथ के लिए भरी गई। इसमें 741 श्रद्धालुओं ने सफर किया। 11 जून व 12 जून को केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने के कारण कुछ ही हेलीकॉप्टर सुबह उड़ पाए। वास्तविकता यह है कि हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान अब इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा कि कहीं अत्यधिक वजन ढोने, कम निचाई पर हेलीकॉप्टर की उड़ान और एक के बाद एक उड़ान भरने के साथ-साथ दूसरी कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है।

हेलीकॉप्टर के इंजन को आराम मिल सके, साथ ही पायलट को भी बीच में अच्छा खासा ब्रेक मिले, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।

उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान पिछले दिनों हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद डीजीसीए ने हेली संचालन से संबंधित कुछ पाबंदी लगाई हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। चारधाम यात्रा में खासकर केदारनाथ धाम में हेली सर्विस के माध्यम से लगातार श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा संचालन केदारनाथ धाम के लिए ही हो रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में इजाफा होने से सरकार और श्रद्धालु दोनों चिंतित है।

बीती 8 मई 2025 को उत्तरकाशी के गंगनानी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत हुई। इस साल की इस यात्रा के दौरान 30 दिनों के भीतर चार हेलीकॉप्टर हादसों में 13 लोगों की जान और करोड़ों रुपये के हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गए है। पर्यटन नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने भी इस बात की पुष्टि की है कि डीजीसीए हेली सर्विस पर रिव्यू कर रहा है। इस रिव्यू के तहत कई तरह की रोक व पाबंदियां भी चारधाम यात्रा पर चल रही हैं। केदारनाथ के लिए उड़ने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को रेग्युलेट भी किया गया है। हादसे से पहले एक घंटे में यात्रियों को लेकर हेलीकॉप्टर 25 से 30 बार उड़ा करते थे, यह उड़ान तीन अलग-अलग जगह से होती थी। लेकिन अब अब मात्र 1 घंटे में 9 से 10 उड़ान भरी जा रही हैं। डीजीसीए ने यह भी साफ किया है कि जिस हेलीकॉप्टर में छह सवारियां यात्रा कर रही थी, उन हेलीकॉप्टर में अब सिर्फ 3 से 4 सवारियां ही यात्रा कर पाएंगी।

इसके साथ ही वजन और मौसम का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही मौसम जरा भी खराब होता है तो कोई भी हेली एजेंसी हेली के संचालन को लेकर दबाव नहीं बनाएगी। डीजीसीए हर एक उड़ान और एविएशन की सारी एक्टिविटी पर नजर रख रहा है। ताकि इस रिव्यू को बेहतर तरीके से किया जा सके और आगे का फैसला लिया जा सके। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद खराब मौसम में हेलीकॉप्टर ने 15 जून की सुबह उड़ान भरी जो दुर्घटना का कारण बन गई और 7 जिंदगियां खत्म हो गईं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा-सूत्र' में है 'भविष्य के भारत की सोच'

लोकेन्द्र सिंह (हि.स.)

पुस्तक समीक्षा

पुस्तकः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा-सूत्र
लेखकः सुनील आंबेकर
मूल्यः 250 रुपये (पेपर बैक)
पृष्ठः 272
प्रकाशकः प्रभात पेपरबैक्स, दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में संघ को लेकर गहरी रुचि और जिज्ञासा सामान्य लोगों से लेकर बौद्धिक जगत में दिखाई दे रही है। संघ के संबंध में अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से लिखा है। इस श्रृंखला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर की पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा-सूत्र' ने प्रकाशन जगत और बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान खींचा है। यह पुस्तक अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। जब संघ की सृष्टि में रचा-बसा लेखक कुछ लिखता है, तब उसे पढ़कर संघ को ज्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह ऐसी पुस्तक है, जो लेखक की प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ विकसित हुई है। संघ की यात्रा और विभिन्न मुद्दों पर संघ का दृष्टिकोण बताते हुए सुनील आंबेकर अपनी संघ यात्रा को भी रेखांकित करते हैं। यह प्रयोग संघ को व्यवहारिक ढंग से समझने में हमारी सहायता करता है। मनोगत में स्वयं लेखक सुनील जी लिखते हैं कि यह पुस्तक उनके लिए है जो व्यवहार रूप में संघ को समझना चाहते हैं, उसके माध्यम से जिसने संघ को जिया है। सुनील आंबेकर का लंबा समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को गढ़ने में भी बीता है। सुनील जी बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं। संघ के साथ उनके संबंध नैसर्गिक रूप से विकसित हुए हैं। नागपुर में उनका घर संघ मुख्यालय के पड़ोस में ही है। उनके घर का द्वार संघ कार्यालय के प्रांगण में ही खुलता था।

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा-सूत्र' पाठकों को न केवल संघ की बुनियादी जानकारी देती है अपितु 'भविष्य के भारत' को लेकर संघ की क्या सोच है, उस पर भी यह पुस्तक बात करती है। पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि पर चर्चा है। संघ की स्थापना के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और उसकी कार्यप्रणाली को ठीक प्रकार से समझना है, तब हमें संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना और जानना चाहिए। इस पुस्तक में यह उल्लेख एक से अधिक स्थानों पर आया है। डॉक्टर साहब क्रांतिकारी संगठनों में रहे, कांग्रेस में भी सक्रिय रहे। वे नागपुर में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। डॉक्टर साहब के पास सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र का समृद्ध अनुभव था, उसी में से उनके हृदय में संघ बीज का प्रस्फुटन हुआ। सुनील जी लिखते हैं, ''डॉक्टर साहब का मानना था कि भारत की गुलामी का कारण केवल विदेशी ताकतें नहीं हैं, जिन्होंने आक्रमण किए अपितु आंतरिक कलह और मतभेद भी इसके कारण रहे हैं। एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी, जहां सब बड़े-छोटे या अन्य लोग किसी भी प्रकार के भेदभाव को भूलकर संवाद कर सकें। इसी विचार ने आगे चलकर शाखा की संकल्पना को जन्म दिया।'' समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से समाज को संगठित करने का पाठ सीखकर डॉक्टर हेडगेवार ने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया, जो व्यक्ति केंद्रित नहीं अपितु तत्व उसके मूल में है।

'संघ की मूल अवधारणाएं' बताते हुए लेखक सुनील जी लिखते हैं, ''जिन मूल केंद्रीय अवधारणाओं से संघ के विचार का जन्म हुआ, ये हैं- राष्ट्रीयता, एकात्मता और सामूहिकता।' वे आगे लिखते हैं, ''संघ के साथ जितना मेरा अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि यह सामंजस्य, विश्वास एवं पारस्परिक आदर का भाव स्थापित करनेवाली और एकत्व स्थापित करनेवाली एक शक्ति है।'' पुस्तक में अन्य स्थानों पर भी संघ की मूल अवधारणाओं की व्याख्या की गई है, उन्हें अलग-अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। संघ के बारे में एक बात सबको समझनी चाहिए कि यह कोई जड़ संगठन नहीं है। समाज के साथ बहनेवाला जीवंत संगठन है, जो देश-काल-परिस्थिति के अनुसार समाज हित में अपने दृष्टिकोण को विस्तार देता है। लेकिन संघ की मूल अवधारणाएं स्थायी हैं, उनमें परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। जैसे-राष्ट्रीयता को लेकर संघ का स्पष्ट मत है कि यह देश 'हिन्दूराष्ट्र' है, संघ इसी अवधारणा के साथ जन्मा और उसी को लेकर आजतक चल रहा है। इस संबंध में पूर्व सरसंघचालक बालासाहब देवरस को उल्लेखित करते हुए वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी कहते हैं, ''जब हमसे पूछा जाता है कि यह कैसे हुआ, वह कैसे हुआ? हमने पहले वैसा कहा था, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बालासाहब ने कहा था कि देखो भाई, हिन्दुस्थान हिन्दूराष्ट्र है, इस एक बात को छोड़कर बाकी सब बदल सकता है, क्योंकि हिन्दुस्थान हिन्दूराष्ट्र है यह किसी के दिमाग की उपजी हुई बात नहीं है। श्री आंबेकर पुस्तक में एक स्थान पर लिखते हैं कि संघ का विचार स्पष्ट और सरल है बेशक कई विद्वानों ने संघ पर कई गहन एवं जटिल ग्रंथ लिखे हैं किंतु केंद्रीय अथवा मूल विचार एक ही है- अच्छे बनो और उस अच्छाई को दूसरों की भलाई के कार्य करते हुए समाज में प्रकट करो।''

संघ की शाखा क्या है, संघ किस प्रकार काम करता है, संगठन की रचना किस प्रकार की है? ये ऐसे प्रश्न हैं, जो उन सबके मन में रहते हैं जो संघ को समझना चाहते हैं। इस सबका उत्तर पुस्तक में मिलता है। वहीं, आजकल बहुत से नेता एवं तथाकथित बुद्धिजीवी भ्रम का वातावरण बनाने के लिए और संघ के प्रति लोगों के मन में संदेह पैदा करने के कपटपूर्ण उद्देश्य से एक प्रश्न उछालते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में संघ का क्या योगदान रहा है? इसका भी तथ्यापूर्ण उत्तर इस पुस्तक में मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि संघ का स्वयंसेवक बनने के बाद स्वयंसेवक एक प्रतीज्ञा करते हैं और उसे बार-बार स्मरण करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व उस प्रतिज्ञा में एक पंक्ति आती थी- मैं हिन्दूराष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए संघ का स्वयंसेवक बना हूं। अब चूंकि स्वतंत्रता मिल गई तो 'हिन्दूराष्ट्र की स्वाधीनता' का स्थान 'हिन्दूराष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति' ने ले लिया। यह एक पंक्ति-एक तथ्य ही, एक अदने से प्रश्न का विराट उत्तर है। इसके बाद भी अन्य तथ्य हमारे सामने पुस्तक में आते हैं, जो बताते हैं कि संघ के स्वयंसेवक न केवल आंदोलन में शामिल रहे अपितु उन्होंने बलिदान भी दिया। जेल की सजा भी काटी। जब पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया, तब संघ ने अपनी सभी शाखाओं पर 26 जनवरी, 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने और प्रभात फेरी निकालने का निर्णय लिया।

कुछ मूढ़मति हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व की मनमानी व्याख्याएं करते हैं। यह लोग हिन्दुत्व को संघ की उपज मानकार, संघ को खारिज करने के साथ-साथ एक नैसर्गिक चिंतन 'हिन्दुत्व' को भी खारिज करने की कोशिशें करते हैं। पांचवे अध्याय 'हिन्दुत्व का पुनरोदय' में लेखक श्री आंबेकर जी ने इस पर विस्तार से चर्चा की है। वह लिखते हैं कि हिन्दुत्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1880 में चंद्रनाथ बसु ने किया, जो एक उप-न्यायाधिकारी एवं लेखक थे। 'हिन्दुत्व' नाम से 1892 में लिखी अपनी पुस्तक में बसु ने हिन्दू धर्म के अंतर्गत समाहित विभिन्न दर्शनों एवं राजनीतिक चिंतन का वर्णन किया है। यहां वह स्पष्ट करते हैं कि हिन्दुत्व शब्द संघ के चिंतन से नहीं जन्मा बल्कि वह तो जीवन जीने की आदर्श पद्धति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। वे लिखते हैं कि ''संघ का विश्वास है कि हिन्दुत्व ज्ञान का ऐसा भंडार है, जिसमें विश्व के सामने मुंह बाए खड़ी सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के मंत्र हैं तथा भारत में व्याप्त अनेक कुरीतियों के उपचार विद्यमान हैं।' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिन्दुत्व राजनीति के लिए नहीं है, यह तो समूची मानवता के कल्याण के लिए है। इसके बाद भी यदि कोई हिन्दुत्व की गलत व्याख्याएं करता है, तब यही मानना चाहिए कि हिन्दू धर्म के प्रति उसके मन में मैल है।

कला-संस्कृति, इतिहास, राजनीति, हिन्दुत्व, जातिगत भेदभाव, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, वैश्विक मुद्दे-आंदोलन, पर्यावरण और परिवार जैसे ज्वलंत विषयों पर भी संघ के दृष्टिकोण को लेकर अपनी पुस्तक में लेखक ने पर्याप्त चर्चा की है। हम जानते हैं कि संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक भारत को परम-वैभव पर देखना चाहता है। वह प्रतिदिन संघ स्थान पर भगवा ध्वज के सामने खड़े होकर प्रार्थना को मंत्र रूप में गाता है और अपने इस संकल्प का घोष करता है। इस संकल्प का विस्तार ही सुनील आंबेकर की पुस्तक 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा-सूत्र' है। यह पुस्तक मूल रूप में अंग्रेजी में 'द आरएसएस : रोडमैप फॉर द 21 सेंचुरी' नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसके विमोचन अवसर पर बहुत ही सारगर्वित उद्बोधन सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी का हुआ था। उनका यह उद्बोधन हिन्दी अनुवाद में 'प्रस्तावना' के रूप में शामिल किया गया है। पुस्तक का अनुवाद डॉ. जितेन्द्र वीर कालरा ने किया है। अनुवाद इतना सहज-सरल है कि कहीं भी विषय का प्रवाह बाधित नहीं होता है। 272 पृष्ठों की इस पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन, दिल्ली ने किया है। संघ की संरचना और उसकी चिंतन प्रक्रिया को समझने में यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

(समीक्षक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।)

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डीसी और पुलिस आयुक्त को मतदान से 72, 48 और 24 घंटे पहले अतिरिक्त सतर्कता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

मतदान से पहले के 72,48 तथा 24 घंटे के दौरान कठोर निगरानी रखी जाए, गर्मी के मद्देनजर मतदाताओं की सुविधा के लिए समूचे प्रबंध करने के निर्देश

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने सोमवार को 64-लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की। इस बैठक में उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु जैन, पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा और रिटर्निंग अधिकारी रूपिंदर पाल सिंह शामिल थे। उपचुनाव प्रक्रिया के इस अंतिम चरण के दौरान, सीईओ ने जिला अधिकारियों को बढ़ी हुई सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए।

बैठक के दौरान, सिबिन सी ने जिला अधिकारियों को मतदान से 72, 48 और 24 घंटे पहले से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सतर्कता और बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 17 जून को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने

के बाद यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के मतदाता और नेता इलाका छोड़ दें। उन्होंने शराब, नकदी, ड्रग्स और अन्य सामग्री की अवैध तस्करी या वितरण को रोकने के लिए 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी को मजबूत करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि यदि मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी या किसी अन्य प्रकार की सामग्री के वितरण की कोई शिकायत मिलती है, तो उस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गर्मी के मद्देनजर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, छबील, प्रतीक्षा क्षेत्र, शौचालय और शेड सहित मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी प्रावधान किए जाएं। उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड -19 सलाह का पालन करने के लिए भी प्रेरित करने की सलाह दी। सिबिन सी ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए मतदान केंद्रों की 100% लाइव वेबकास्टिंग, साथ ही मतदान केंद्रों, स्ट्रांग रूम, मतगणना हॉल और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी पूरी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर चुनाव आयोग के दिशानिदेर्शों के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाए। उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस आयुक्त ने सीईओ को सूचित किया कि उपचुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, और चुनाव आयोग के निदेर्शों के अनुसार चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज की बैठक में दिए गए सभी निदेर्शों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान अतिरिक्त सीईओ हरीश नैयर, संयुक्त सीईओ सकतर सिंह बल, चुनाव अधिकारी अंजू बाला और सीईओ कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कुल मतदाता, संवेदनशील और मतदान केंद्रों की संख्या

सिबिन सी ने बताया कि लुधियाना पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,74,437 मतदाता हैं, जिनमें 89,602 पुरुष मतदाता, 84,825 महिला मतदाता और तीसरे लिंग के रूप में पहचाने जाने वाले 10 मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए 66 स्थानों पर कुल 194 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 10 मॉडल मतदान केंद्र, महिलाओं द्वारा संचालित एक मतदान केंद्र, एक पर्यावरण-अनुकूल ₹हरा₹ मतदान केंद्र और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा संचालित एक मतदान केंद्र शामिल है। इसके अतिरिक्त, 13 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बुजुर्ग, दिव्यांग और किसी भी बीमारी से पीड़ित मतदाताओं की सुविधा के लिए उनके घरों पर जाकर मतदान कराया गया है, जिसमें कुल 239 मतदाताओं ने भाग लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, और 23 जून को सुबह 8 बजे खालसा कॉलेज फॉर वुमेन, लुधियाना में मतों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसे मतगणना केंद्र बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 54 नाकाबंदी की गई है और सुरक्षा बल सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए सफाई इंस्पेक्टर विजिलेंस ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों काबू

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अपनी मुहिम के तहत नगर काउंसिल जलालाबाद, जिला फाजिल्का में तैनात सैनिटेशन इंस्पेक्टर गुरबिंदर सिंह को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जलालाबाद के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त इंस्पेक्टर ने शहर में उसके द्वारा किए गए सफाई कार्यों के बिल पास करने के बदले उससे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, लेकिन अनुरोध करने पर वह 15,000 रुपये लेने के लिए राजी हो गया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस

ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया। इस संबंध में नगर काउंसिल के उक्त कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत विजिलेंस ब्यूरो के थाना फिरोजपुर रेंज में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है।

पंजाब कैबिनेट सब-कमेटी ने की 12 कर्मचारी यूनियनों से बैठकें

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने आज यहाँ लगभग एक दर्जन कर्मचारी यूनियनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करते हुए उनकी माँगों व मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर कमेटी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जायज मुद्दों के समाधान हेतु समयबद्ध ढंग से आवश्यक कार्रवाइयाँ तेज की जाएँ।

पंजाब सिविल सचिवालय स्थित वित्त मंत्री के कार्यालय में लगभग चार घंटे तक चली बैठकों में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल और डॉ. रवजोत सिंह द्वारा विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों से सार्थक संवाद किया गया।

बैठकों में भाग लेने वाली यूनियनों में कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन, सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे मील दफ्तरी कर्मचारी

यूनियन, पीएस टैट पास डीपीई यूनियन, बेरोजगार पीएस टैट आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, आदर्श स्कूल टीचिंग व नॉन-टीचिंग कर्मचारी यूनियन, पावरकॉम ट्रांसको आउटसोर्स वर्कर यूनियन, मानभत्ता वर्कर साझा मोर्चा, पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन, जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे पैरिटी तथा पंजाब रोडवेज स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन शामिल थीं।

बैठकों के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियन नेताओं द्वारा सौंपे गए माँग पत्रों में उठाए गए बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों को कर्मचारियों की जायज माँगों के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी, व्यय सचिव वी.एन. जादे, परिवहन सचिव वरुण रूजम, कार्मिक सचिव गुरप्रीत कौर सपरा और शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा को उनके विभागों से संबंधित माँगों पर समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

बैठकों में भाग लेने वाले यूनियन प्रतिनिधियों में कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी से जोली सिंगला, कुलदीप सिंह, कुलविंदर सिंह; सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस से देव राज वर्मा, मख्खन सिंह, जसमेर कौर; सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे मील दफ्तर कर्मचारी यूनियन से रजिंदर सिंह, परवीन शर्मा, जगमोहन सिंह; पीएस टैट पास डीपीई यूनियन से रमनप्रीत सिंह, मलकीअत सिंह, हरदीप सिंह; बेरोजगार पीएस टैट आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन से राकेश कुमार, हरबंस सिंह, किरणदीप कौर; डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट से विक्रम देव सिंह, महिंदर कुमार, डॉ. टीना; आदर्श स्कूल टीचिंग व नॉन-टीचिंग यूनियन से जसबीर सिंह, अमरजोत जोशी, सुखदीप कौर; पावरकॉम ट्रांसको आउटसोर्स वर्कर यूनियन से हरविंदर शर्मा, मनदीप सिंह, मनदीप कौर; मानभत्ता वर्कर साझा मोर्चा से ममता शर्मा, मनदीप कौर, शकुंतला शर्मा; पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन से गुरनाम सिंह विरक, तरसेम सिंह, अनुज कुमार; जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे पैरिटी से डॉ. जतिंदर सिंह, डॉ. पुनीत, डॉ. जसलीन कौर तथा पंजाब रोडवेज स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन से हरमिंदर सिंह व उनके साथी शामिल थे।

डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में नशे से प्रभावित युवाओं के लिए नए कौशल विकास कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए

संवाददाता
जालंधर

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने बेरोजगारी को खत्म करने और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास कोर्स के तहत अधिक से अधिक पहलकदमिया करने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण (रूडसैट) संगठन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डा.अग्रवाल ने सभी विभागों को विभिन्न योजनाओं और प्रोग्रामों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करने को कहा। डिप्टी कमिश्नर ने रूडसैट संस्थान को मॉडल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में नशे की लत से पीड़ित युवाओं को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए नए प्रशिक्षण कोर्स पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास प्रोग्राम इन

युवाओं के लिए नई उम्मीद की किरण हैं और इन कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके वह सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। उन्होंने रोजगार विभाग को कुशल युवाओं को स्व-रोजगार या नौकरियों के माध्यम से उचित प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। रुडसैट संस्थान के डायरेक्टर संजीव कुमार चौहान ने त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कि कहा कि हाल ही में 36 प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किए गए है, जिनमें से 1000 युवाओं ने लाभ उठाया है और 709 युवाओं ने नौकरी या स्व-रोजगार शुरू किया है। उन्होंने कहा कि संस्थान की स्थापना के बाद से, 503 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए है, जिसके दौरान 13000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। डा. अग्रवाल ने रोजगार के लिए उद्योगों की मांग के अनुसार नए कोर्स शुरू करने के लिए भी कहा। बैठक के अंत में, डा. अग्रवाल ने संगठन द्वारा प्राप्त अद्वितीय उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को दशार्ते हुए वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट भी जारी की।

नशा छुड़वाने के प्रयासों के तहत 55 व्यक्तियों को इलाज के लिए किया गया रजामंद

संवाददाता
चंडीगढ़

युद्ध नशों विरुद्ध के 107वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 102 नशा तस्कर गिरफ़्तार; 688 ग्राम हैरोइन और 26 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों पर राज्य से नशों का पूरी तरह खात्मा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे युद्ध नशों विरुद्ध के 107वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 102 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया और उनके कब्जे से 688 ग्राम हैरोइन, 105 किलो भुक्की, 2164 नशे की गोलियाँ तथा 26,910 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इस प्रकार अभियान के मात्र 107 दिनों में कुल गिरफ़्तार किए गए तस्करों की संख्या 17,749 तक पहुँच चुकी है।

यह ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के निदेर्शों के तहत राज्य के सभी 28 जिलों में एक साथ चलाया गया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाया जाए।

इसके साथ ही नशों के विरुद्ध इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है।

ऑपरेशन की जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीपी (कानून और व्यवस्था) अरपित शुक्ला ने बताया कि 95 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 1400 से अधिक पुलिसकर्मियों की भागीदारी वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 479 स्थानों पर छापेमारी की।

इस दौरान राज्य भर में 76 एफआईआर दर्ज की गईं। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 504 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

स्पेशल डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए लागू की गई तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), पुनर्वास (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) – के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 55 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास इलाज के लिए प्रेरित किया है।

फैसले से आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत; निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर नागरिक ले सकेंगे लाभ: लालजीत भुल्लर

पंजाब सरकार ने आरसी और डीएल के बैकलॉग संबंधी लिया बड़ा फैसला; क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए गए पंजीकरण अधिकार

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंसों (डीएल) के पंजीकरण और नवीनीकरण के अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य आरसी और डीएल पंजीकरण तथा नवीनीकरण के वर्षों से लंबित बैकलॉग कार्य को पूरा करना है और आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करना है।

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के नागरिक एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर इस राहत का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपने पुराने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करवा सकते हैं और संबंधित दस्तावेजों का नवीनीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने आरसी और डीएल के नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेजों की स्वीकृति और उनका ऑनलाइन न होना एक बड़ी बाधा बना हुआ था।

मंत्री ने बताया कि पंजाब के सभी पंजीकरण अधिकारियों और लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक लिखित पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और बैकलॉग को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा 24 मई, 2024 को जारी पत्र की शर्तों के अनुसार निपटाने के लिए कहा गया है।

स. भुल्लर ने बताया कि आरसी और डीएल के बैकलॉग के संबंध में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हलफनामा लिया जाएगा। इस हलफनामे में बैकलॉग के माध्यम से ऑनलाइन कराने, अवधि, श्रेणी, मैनुअल जारी करने वाले प्राधिकरण, द्वारा चेसिस और इंजन नंबर के पूरे विवरण के साथ भौतिक जांच रिपोर्ट भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आरसी बैकलॉग करते समय विभिन्न व्यक्तियों के वाहन हस्तांतरण रिकॉर्ड भी अपलोड किए जाएं, ताकि पिछले मालिकों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जा सके।

स. भुल्लर ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के बैकलॉग के संबंध में, आवेदन मूल प्राधिकरण के माध्यम से किया जा सकेगा। डीलिंग स्टाफ कार्यालय रिकॉर्ड से पहले और बाद में जारी किए गए लाइसेंस की प्रमाणित/सत्यापित प्रति को सारथी सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा, जिसके बाद लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान कर भुगतान और कोई बकाया न होने तथा सभी जानकारी के सही होने संबंधी प्रविष्टि करनी होगी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि आरसी के बैकलॉग को ऑनलाइन करते समय, जिस वाहन पर पंजीकरण नंबर लगा है, उसका मोटर वाहन निरीक्षक लाइसेंस की मूल प्रति और जन्म/पते के प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। मंत्री ने बताया कि बैकलॉग के कार्य को पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए विभाग का एक स्थायी कर्मचारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस/आरसी से संबंधित बैकलॉग की प्रविष्टि कार्यालय में दर्ज करेगा, उसे परिवहन पोर्टल पर सत्यापित करेगा, और इसके बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी गलत प्रविष्टि की पूरी जिम्मेदारी संबंधित पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण की होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरसी और डीएल बैकलॉग अनुमोदन की दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय को निर्धारित प्रोफार्मा में भेजी जाए।

संक्षिप्त-समाचार

बिलीव ने किया हरियाणवी म्यूज़िक के लिए नया प्लेटफॉर्म म्हारा टोरा लॉन्च

चंडीगढ़/अंबाला। दुनिया की जानी-मानी डिजिटल म्यूज़िक कंपनी बिलीव ने भारत में हरियाणवी म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए नया प्लेटफॉर्म म्हारा टोरा लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश हरियाणा के कलाकारों को आगे बढ़ाना है, ताकि उन्हें म्यूज़िक बनाने की पूरी आजादी के साथ-साथ मार्केटिंग, डिजिटल और आर्थिक मदद भी मिल सके। म्हारा टोरा बिलीव इंडिया की आर्टिस्ट सर्विसेज टीम का हिस्सा है, और ये हरियाणा के कुछ नए और जाने-माने कलाकारों के साथ मिलकर काम करेगा। इस नए इम्प्रिन्ट के तहत बिलीव ने 8 बड़े हरियाणवी कलाकारों को साइन किया है, जिनमें शामिल हैंः कबीरा, अजय भगता, काका हफ्छऊ जीपी जी, हैशटैग पंडित, अमित सैनी रोहतकिया, अमित धुल और रेणुका पंवार। इसका उद्देश है हरियाणवी म्यूज़िक को भारत और विदेशों में ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। बिलीव अपनी डिजिटल ताकत और म्यूज़िक ऐप्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए इस म्यूज़िक को और बड़ा बनाएगा। थाईलैंड, इटली और फ्रांस में भी बिलीव ने ऐसे ही प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, और अब भारत में हरियाणवी संगीत के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बिलीव इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक रैना ने कहाः हरियाणवी म्यूज़िक आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। म्हारा टोराके जरिए हम चाहते हैं कि यहां के कलाकारों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिले, जिससे वो अपने गाने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।

नीट यू जी 2025 में छाए आकाश इंस्टिट्यूट चंडीगढ़ के छात्र

चंडीगढ़। ःआकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (ए.ई.एस.एल), जो भारत में परीक्षा-पूर्व तैयारी सेवाओं में अग्रणी संस्था है, ने आज घोषणा की कि उसके 15 छात्रों ने चंडीगढ़ से नीट (एन.ई.ई.ट) यू जी 2025 परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष रैंक हासिल की है। यह सफलता छात्रों की प्रतिबद्धता, अनुशासित अध्ययन और ए.ई.एस.एल द्वारा प्रदान किए गए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन का परिणाम है। परीक्षा के परिणाम कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए) द्वारा घोषित किए गए। जनव बंसल ने ऑल इंडिया रैंक (ए.आई.आर) 89, अधिराज सिंह पनाग ने ऑल इंडिया रैंक (ए.आई.आर) 103 प्राप्त कर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। अन्य उल्लेखनीय रैंक धारकों में आरव गोयल (ए.आई.आर), युवराज घई (ए.आई.आर), अमीषी मंगल (ए.आई.आर 1833), पारस कम्बोज (ए.आई.आर 2945), इशिता शर्मा (ए.आई.आर 3229), देवांश (ए.आई.आर 4450) और प्रीतम सिंह (ए.आई.आर 6774) शामिल हैं। ये छात्र ए.ई.एस.एल के क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े थे, जो विशेष रूप से नीट जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय संस्थान द्वारा दी गई मजबूत अकादमिक नींव, अवधारणात्मक स्पष्टता और नियमित अभ्यास को दिया। छात्रों ने साझा किया,ह्लहम आकाश का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और सुव्यवस्थित अध्ययन सामग्री ने हमें कठिन विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। विशेषज्ञ शिक्षकों और व्यक्तिगत मार्गदर्शन ने हमारी सफलता में अहम भूमिका निभाई।ह्व डॉ. सुरेन्द्र चौहान, रीजनल डायरेक्टर, ए.ई.एस.एल , ने कहा,ह्लहमारे छात्रों ने नीट (एन.ई.ई.ट) यू जी 2025 में जिस उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है, उस पर हमें गर्व है। यह न केवल छात्रों के अथक प्रयासों का परिणाम है, बल्कि उनके माता-पिता और हमारे शिक्षकों के समर्पण का भी प्रतीक है। हम छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।ह्व

निसान मोटर इंडिया ने नेटवर्क विस्तार को दी गति

चंडीगढ़। निसान मोटर इंडिया ने राजस्थान में पांच नए टचपॉइंट्स की लॉन्चिंग के साथ भारत में अपना नेटवर्क 283 कस्टमर टचपॉइंट्स तक पहुंचने की घोषणा की है। इस विस्तार से प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों में सुगमता और ग्राहकों के बेहतर अनुभव पर ब्रांड के फोकस को मजबूती मिलेगी। नए लॉन्च किए गए टचपॉइंट्स में जयपुर में एक शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, उदयपुर में व्यापक 3एस सेंटर और अजमेर में एक नया शोरूम शामिल है। उदयपुर के 3एस सेंटर में एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स ऑपरेशंस का परिचालन होगा। नए केंद्रों का उद्घाटन निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सौरभ वत्स ने किया। यहां कुशल एवं उत्साही सेल्स एवं सर्विस प्रोफेशनल्स को नियुक्त किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हर टचपॉइंट को इस तरह डिजाइन किया गया है, जिससे ग्राहकों को सुगम और शानदार ब्रांड एक्सपीरियंस मिले। निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने कहा, जयपुर, उदयपुर और अजमेर में नई डीलरशिप के उद्घाटन के साथ राजस्थान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का हमें गर्व है। हम भारत में अपने फ्यूचर पोर्टफोलियो की लॉन्चिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं और ये उद्घाटन उसी दिशा में हमारे नेटवर्क विस्तार के प्रयासों का हिस्सा हैं। यह सांस्कृतिक रूप से जीवंत और आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य में ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दशार्ता है। राजस्थान एक महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव बाजार के रूप में उभर रहा है और हमारा उद्देश्य केवल वाहन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि इनोवेशन, क्वालिटी एवं भरोसे के साथ सार्थक अनुभव प्रदान करना भी है। हम यहां अपने ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाने और मोबिलिटी के उनके सफर का हिस्सा बनने के लिए प्रयासरत हैं।

'नेशनल सर्जन्स डे' पर समर्पित सर्जिकल टीम सम्मानित

चंडीगढ़। 'नेशनल सर्जन्स डे' के अवसर पर पारस हेल्थ ने अपनी समर्पित सर्जिकल टीम को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम पारस हेल्थ की देशव्यापी पहल का हिस्सा था, जो गुरुग्राम, कानपुर, पटना, दरभंगा, उदयपुर, जयपुर, उज्जैन, रांची और श्रीनगर सहित अन्य केंद्रों पर भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फैसिलिटी डायरेक्टर डॉ. पंकज मित्तल के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ और मरीजों ने भाग लिया। इस अवसर पर अस्पताल के 22 सर्जनों को उनके उत्कृष्ट इलाज, नेतृत्व और ऑपरेशन थियेटर के अंदर और बाहर दिए गए योगदान के लिए सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई छोटे वैज्ञानिक सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें सर्जनों ने जटिल सर्जरी और चिकित्सा क्षेत्र में हाल की प्रगति पर अपने विचार साझा किए। इन सत्रों से टीम की विशेषज्ञता और नवाचार की झलक सामने आई। मरीजों की भावनात्मक कहानियों ने कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। कुछ मरीजों ने मंच से, तो कुछ ने वीडियो संदेशों के माध्यम से बताया कि समय पर की गई सर्जरी ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। इन संदेशों ने डॉक्टरों के प्रति उनके गहरे विश्वास और आभार को उजागर किया। इस अवसर पर डॉ. पंकज मित्तल ने कहा, सर्जन होना सिर्फ सर्जरी करना नहीं है, बल्कि यह लोगों के सबसे कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने का नाम है। पारस हेल्थ में हम एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, और हर सफलता साझेदारी, विश्वास और निरंतर सीखने का परिणाम होती है। पारस हेल्थ निरंतर अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल की ₹पेशेंट फर्स्ट₹ नीति इस बात को सुनिश्चित करती है कि हर मरीज को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा और मानवता से भरा उपचार मिले।

इनड्राइव देता है यात्रियों को किराया तय करने की आजादी

चंडीगढ़। इनड्राइव एक ग्लोबल मोबिलिटी और शहरी सेवाओं का प्लेटफॉर्म, अब चंडीगढ़ में राइड-हेलिंग इंडस्ट्री को एक नया और अनोखा अनुभव दे रहा है। इनड्राइव की सबसे खास बात है इसका बारगेनिंग फीचर, जो यात्रियों और ड्राइवरों को किराया तय करने की पूरी आजादी देता है। जहां बाकी ऐप्स में किराया फिक्स होता है, वहीं इनड्राइव अकेला ऐसा ऐप है जो चंडीगढ़ में दो-तरफा मोलभाव की सुविधा देता है। यात्री और ड्राइवर दोनों ऐप पर एक-दूसरे से बातचीत करके सफर का दाम तय करते हैं। यह मॉडल पारदर्शिता, विकल्प और न्याय को प्राथमिकता देता है कृ ताकि हर राइड इंसानों के आपसी समझ से तय हो, न कि किसी मशीन के फिक्स सिस्टम से। इनड्राइव पर कोई फिक्स किराया नहीं होता। यहां यात्री ऐप के जरिए खुद अपना किराया तय कर सकते हैं, जिससे पास के ड्राइवरों के साथ रियल-टाइम में मोलभाव शुरू होता है। ड्राइवर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं, नई रकम का ऑफर दे सकते हैं या मना भी कर सकते हैं। यह इन-ऐप मोलभाव फीचर यात्रियों और ड्राइवरों - दोनों को बराबरी का हक देता है कि वे मिलकर एक आपसी सहमति वाला किराया तय करें। यह लचीलापन और न्याय की भावना देता है, जो पारंपरिक राइड-हेलिंग सेवाओं में बहुत कम देखने को मिलती है। इनड्राइव ने सर्ज प्राइसिंग और जटिल एल्गोरिदम को हटाकर एक खुले मोलभाव वाले मॉडल को अपनाया है, जो पारदर्शिता और बराबरी को बढ़ावा देता है। अब यूजर्स किसी ऑटोमैटिक प्राइस सिस्टम पर निर्भर नहीं हैं। इसके बजाय, वे एक ऐसे मॉडल का हिस्सा बनते हैं जो चॉइस, सहमति और कंट्रोल पर आधारित है - जहां हर राइड एक फेयर डील होती है।

योगी सरकार का महिला सुरक्षा का वादा देश के लिए बना रोल मॉडल

एक बार फिर योगी सरकार ने महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में मारी बाजी

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

भारत सरकार के इंवेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल अफेंस (आईटीएसएसओ) की जून माह की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर बड़े राज्यों में महिला संबंधी यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों के कॉम्प्लाएंस रेश्यो में भी बड़े राज्यों में यूपी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। देश में उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में पेंडेंसी सबसे कम है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों की पेंडेंसी को जीरो करने के निर्देश दिये हैं। बता दे कि योगी सरकार पिछले कई वर्षों से महिला संबंधी अपराधों के डिस्पोजल रेट, कंप्लायंस रेट में पहले स्थान पर बना हुआ है।

पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश पूरे देश में शीर्ष स्थान पर, वर्ष 2018 से पहले सातवें और दसवें स्थान पर था

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की नोडल पद्मजा चौहान ने बताया कि आईटीएसएसओ की 21 अप्रैल 2018 से तीन जून-2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराधों के निस्तारण में देश भर के राज्यों में पहले स्थान पर है। प्रदेश का निस्तारण रेश्यो 98.60 प्रतिशत है इस दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 1,22,130 एफआईआर दर्ज की गयी। वहीं केंद्र शासित राज्यों में दादरा और नगर हवेली व दमन एवं दीव 98.80 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है।

फोटोः हि.स.

उन्होंने बताया कि अगर देश के बड़े राज्यों की बात करें तो महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश पहले, दिल्ली 97.60 प्रतिशत के साथ दूसरे और हरियाणा 97.20 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में सातवें स्थान पर था। उस समय मामलों के निस्तारण की दर 95 प्रतिशत थी।

इसी तरह कंप्लायंस रेट (60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की दर) में गोवा 88.50 प्रतिशत के साथ पहले, दादरा और नगर हवेली व दमन एवं दीव 88.30 प्रतिशत के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 80.60 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश 80.60 प्रतिशत के साथ पहले, उत्तराखंड 80 प्रतिशत के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 77 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है जबकि वर्ष 2018 में प्रदेश इस रैंकिंग में दसवें स्थान पर था।

नोडल अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश का पेंडेंसी रेट (लंबित मामलों का अनुपात) केवल 0.20 प्रतिशत है, जो इसे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाता है। वहीं मणिपुर, तमिलनाडु और बिहार का पेंडेंसी रेट काफी अधिक (मणिपुरः 65.7 प्रतिशत, तमिलनाडुः 58.0 प्रतिशत और बिहार 34.5 प्रतिशत) है जबकि वर्ष 2018 में इस रैंकिंग में प्रदेश सातवें स्थान पर था। यह उपलब्धि योगी सरकार की नेतृत्व क्षमता और महिला सुरक्षा के प्रति सख्त नीति को दर्शाती है। नोडल ने बताया कि महिला संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए डब्ल्यूसीएसओ (वूमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी आगेर्नाइजेशन) द्वारा हर महीने केसों की समीक्षा की जाती है।

इसके साथ जिलों और कमिश्नरेट स्तर पर एएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा पॉक्सो मामलों की कड़ी निगरानी, लंबित मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियमित फॉलोअप, दो माह से अधिक लंबित केस वाले आईओ को मुख्यालय बुलाकर व्यक्तिगत समीक्षा, आईओ के लिए नियमित ट्रेनिंग और कानूनी कार्यशालाओं का आयोजन, समय पर जांच पूरी करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र और लापरवाही बरतने वाले आईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। इसी का नतीजा है कि आज इसके परिणाम हम सबके सामने हैं।

मुख्यमंत्री ने मीठापुर-महुली-पुनपुन परियोजना एलिवेटेड/एटग्रेड सड़क का किया लोकार्पण

एजेंसी (हि.स.)
पटना

फोटोः हि.स.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना जिला के भूपतिपुर में आयोजित कार्यक्रम स्थल से मीठापुर-महुली-पुनपुन परियोजना अंतर्गत 1105 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भूपतिपुर से पुनपुन (एनएच-22) तक एलिवेटेड/एटग्रेड पथांश का लोकार्पण किया।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पथ के निर्माण से गयाजी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और राजगीर जाने में लोगों को सुविधा होगी। साथ ही दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में आना-जाना भी अब बेहद आसान हो जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि पटना को जाम मुक्त बनाने और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में यह एलिवेटेड सड़क काफी उपयोगी होगी। इस एलिवेटेड सड़क के शुरू होने से राजधानी के दक्षिणी इलाकों में रहनेवाले लाखों लोगों को यातायात में काफी सहूलियत होगी एवं आवागमन में समय की बचत होगी।

मुख्यमंत्री लौटने के क्रम में सिपारा के पास रुके। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि मीठापुर-महुली एलिवेटेड का निर्माण सिपारा पुल के ऊपर से होगा और मीठापुर फ्लाईओवर गोलंबर पर आकर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बचे हुये कार्य को दो माह में पूर्ण करें। सिपारा से महुली एलिवेटेड पथ पर जाने के लिए भूपतिपुर के पास बने रैंप से होकर लोग अब सफर कर सकेंगे और सिपारा से महुली की दूरी महज 5 से 6 मिनट में पूरी हो जाएगी।

लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित एलिवेटेड/एटग्रेड पथांश का भूपतिपुर से पुनपुन तक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुनपुन में रुके और वहां उपस्थित लोगों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा।

रूस ने अपने नागरिकों से तत्काल इजराइल छोड़ने का आग्रह किया, मिस्र के रास्ते लौटने की सलाह

एजेंसी (हि.स.)
मॉस्को

फोटोः हि.स.

इजराइल के तेल अवीव में स्थित रूस के दूतावास ने अपने नागरिकों से तत्काल इजराइल छोड़ने का आग्रह किया है। राजदूत अनातोली विक्टरोव ने आज रूसी मीडिया से कहा कि इजराइल और ईरान के बीच पिछले सप्ताह के अंत से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। ऐसे में रूस के नागरिकों का इजराइल में रहना खतरे से खाली नहीं है।

द मास्को टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार विक्टरोव ने रोसिया 24 प्रसारक से कहा, 'इजराइल में मौजूद सभी रूसी नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक देश छोड़ देना चाहिए।' उन्होंने रूस के नागरिकों को मिस्र के रास्ते लौटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मिस्र से रूस के नागरिक बिना वीजा के मॉस्को के लिए उड़ान भर सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'स्थिति तनावपूर्ण है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। इजराइल में राजनयिकों और रूसी नागरिकों दोनों के जीवन के लिए काफी खतरा है।' राजदूत ने कहा कि व्यापक निकासी की आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। सप्ताहांत में तेहरान में रूस के दूतावास ने अपने वाणिज्य दूतावास में गतिविधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर अपने नागरिकों के एक समूह को रूस वापस बुला लिया है।

पाकिस्तान ने ईरान-इजराइल तनाव की वजह से 16 उड़ानें रद्द की

इस्लामाबाद। ईरान और इजराइल के बीच बढ़े सैन्य तनाव के कारण पाकिस्तान, इराक और कतर सहित कई देशों में अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन बाधित हो गया है। पाकिस्तान ने कम से कम 16 उड़ानें रद्द कर दी हैं। कराची में क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण जेद्दा, मशहद, बगदाद और तेहरान के लिए आठ उड़ानें रद्द की गई हैं। विदेशी एयरलाइन की इस्लामाबाद से नजफ के लिए दो उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान के दुनिया न्यूज चैनल की खबर में यह जानकारी दी गई। चैनल ने दावा किया है कि इसके अलावा, जेद्दा, दुबई, बहरीन और रस अल खैमाह से इस्लामाबाद के लिए उड़ानें भी देरी का सामना कर रही हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बीच सऊदी एयरलाइंस ने आज और 17 जून के लिए ईरान और इराक के लिए निर्धारित सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसी तरह, रूस, लेबनान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान के लिए उड़ानें भी रोक दी गई हैं। कतर एयरवेज ने ईरान, इराक और सीरिया के लिए अपने परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

इजराइली हमले में मारे गए ईरान के तीन शीर्ष खुफिया अधिकारी

सर्वोच्च नेता खामेनेई को भूमिगत बंकर में ले जाया गया

एजेंसी (हि.स.)
तेहरान

फोटोः हि.स.

इजराइल के मिसाइल हमले में रविवार को ईरान के तीन शीर्ष खुफिया अधिकारी मारे गए। इनके नाम मोहम्मद काजमी, हसन मोहक्कक और मोहसेन बाकरी हैं। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का कोई अता-पता नहीं है। समझा जा रहा है कि उन्हें ईरान के सबसे सुरक्षित भूमिगत बंकर में छुपा दिया गया है।

इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कोर से संबद्ध ईरान की सरकारी संवाद समिति 'तस्नीम न्यूज' ने तीन शीर्ष खुफिया अधिकारियों के मारे जाने की पुष्टि की है। 'तस्नीम' की खबर के अनुसार, 15 जून को हुए इजराइल के मिसाइल हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख जनरल मोहम्मद काजमी, उप प्रमुख जनरल हसन मोहक्कक और जनरल मोहसेन बाकरी शहीद हो गए।

इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन ने बयान में तीनों अधिकारियों की मौत पर शोक जताया है। बयान में आरोप लगाया है कि इजराइल आवासीय क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। आवासीय क्षेत्रों पर हमला आतंकवादी प्रवृत्ति है। इजराइली हमलों में 13 जून से अब तक सैन्य अधिकारियों, परमाणु वैज्ञानिकों और आम लोगों सहित दर्जनों ईरानियों की जान जा चुकी है।

इस बीच, इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा है कि उसके सुरक्षा बलों ने ईरान में हथियार बनाने वाले कई कारखानों को मिट्टी में मिला दिया। साथ ही ईरानी सेना के तीन आला अफसरों को मार गिराया।

संक्षिप्त-समाचार

आईएमएफ की शीर्ष अधिकारी डॉ. गीता गोपीनाथ ने राष्ट्रपति से श्रीलंका के आर्थिक सुधार पर की चर्चा

कोलंबो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रथम उप प्रबंध निदेशक डॉ. गीता गोपीनाथ ने आज कोलंबो में राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) के गवर्नर डॉ. नंदलाल वीरसिंघे से मुलाकात की। डॉ. गीता गोपीनाथ ने दोनों से श्रीलंका के आर्थिक सुधार प्रयासों पर चर्चा की। डेली मिरर अखबार की खबर के अनुसार डॉ. गोपीनाथ ने सबसे पहले राष्ट्रपति दिसानायके से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आर्थिक सुधारों को लागू करने में श्रीलंका की उत्साहजनक प्रगति पर चर्चा की। डॉ. गोपीनाथ ने एक्स पोस्ट पर कहा कि उन्हें राष्ट्रपति से मिलकर खुशी हुई। चर्चा श्रीलंका के आर्थिक सुधारों पर मजबूत प्रदर्शन और इस गति को बनाए रखने के महत्व पर केंद्रित रही। आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक डॉ.गोपीनाथ ने कहा कि इन सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता सभी श्रीलंकाई लोगों के लिए स्थायी स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद डॉ. गोपीनाथ ने सीबीएसएल के गवर्नर डॉ. नंदलाल वीरसिंघे के साथ चर्चा की। उन्होंने बैठक को उत्कृष्ट बताया। उल्लेखनीय है 08 दिसंबर, 1971 को जन्मीं गीता गोपीनाथ भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। वह 21 जनवरी, 2022 से आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर हैं।

ब्रिटिश उच्चायुक्त सारा कुक ने बांग्लादेश में बीएनपी नेताओं से मुलाकात की

ढाका। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों पर मचे घमासान के बीच आज ब्रिटिश उच्चायुक्त सारा कुक ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। लगभग एक घंटे तक चली यह मुलाकात बंद कमरे में हुई। ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार की खबर के अनुसार सारा कुक ने बीएनपी मुख्यालय गुलशन में पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से आगामी राष्ट्रीय चुनाव और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बीएनपी मीडिया सेल के सदस्य सैरुल कबीर खान ने बताया कि सुबह करीब साढ़े दस बजे बैठक शुरू हुई जो एक घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य डॉ. अब्दुल मोईन खान और आयोजन सचिव शमा ओबैद भी मौजूद रहे। खान और ओबैद पार्टी प्रमुख की विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

जम्मू-कश्मीर की चेरी हुई वैश्विक, पहली अंतरराष्ट्रीय खेप को दिखाई गई हरी झंडी

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तत्वावधान में प्रीमियम गुणवत्ता वाली कश्मीरी चेरी की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप को आधिकारिक तौर पर रवाना किया गया, जो वैश्विक ताजा उपज बाजारों में घाटी के प्रवेश करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को 'एक्स' पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि जम्मू-कश्मीर से प्रीमियम चेरी की पहली वाणिज्यिक खेप सऊदी अरब और यूएई के लिए रवाना हुई। इससे हमारे चेरी किसानों के लिए एक बड़ा बाजार खुल गया है, जिन्हें अब अपनी उपज के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। पीयूष गोयल ने आगे लिखा है मोदी सरकार भारत को प्रीमियम कृषि उत्पादों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए रसद संबंधी कमियों को दूर करने में जुटी है। ये उपलब्धि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तत्वावधान में हासिल की गई है। ताजा चेरी की यह पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को निर्यात की जा रही है, जो कश्मीरी बागवानी उत्पादों के लिए एक संरचित वैश्विक निर्यात पाइपलाइन की शुरूआत है।

बांग्लाभाषी भारतीय नागरिकों को 'बांग्लादेशी' बता रही भाजपाः ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला बोलने वाले भारतीय नागरिकों को 'बांग्लादेशी' करार दिया जा रहा है। उन्होंने इसे भाषा के आधार पर 'विचहंट' (राजनीतिक उत्पीड़न) करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'आपको शर्म आनी चाहिए कि आप केवल भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बता रहे हैं। बांग्ला, गुजराती, मराठी और हिंदी- ये सभी भाषाएं हमारी पहचान हैं। मैं सभी भाषाएं बोल सकती हूं और मुझे इस पर गर्व है।' उन्होंने आगे कहा, 'भाषा के आधार पर लोगों को बांग्लादेशी ठहराया जा रहा है और जिनके पास वोटर आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे वैध दस्तावेज हैं, उन्हें रोजगार के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।' ममता बनर्जी की इस टिप्पणी के बाद भाजपा विधायकों ने विरोध जताया और नारेबाजी शुरू कर दी, इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अपना भाषण में अडिग जारी रखा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद राज्य सरकार ने 'पथश्री' योजना के तहत 69 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और ₹11 हजार करोड़ की लागत से आवास योजना शुरू की है। उन्होंने दावा किया कि 'पश्चिम बंगाल लगातार पांच वर्षों से सड़क और ग्रामीण आवास योजनाओं की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है।'

युवक को ट्रक ने रौंदा, मौत

सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर सड़क पार कर रहा युवक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राबर्ट्सगंज कोतवाल ने सोमवार को बताया कि सुकृत निवासी नीरज प्रजापति (31) पुत्र विश्राम प्रजापति बीती रात लगभग साढे. आठ बजे सड़क पार कर सामान लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह सड़क पार करने लगा, तभी राबर्ट्सगंज से वाराणसी की तरफ जा रहे ट्रक ने उसे रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को आसपास के लोगों ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में डाक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत देख वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर वाराणसी जा रहे थे तभी रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

थोक महंगाई दर मई में घटकर 14 महीने के निचले स्तर 0.39 फीसदी पर

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को बड़ी मिली है। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में भी गिरावट आई है। मई महीने में थोक महंगाई दर घटकर 0.39 फीसदी पर आ गई है, जो इसका 14 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले अप्रैल में थोक महंगाई दर 0.85 फीसदी रही थी, जबकि पिछले साल मई में यह 2.74 फीसदी थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित थोक महंगाई दर मई महीने में घटकर 0.39 फीसदी पर आ गई है। रोजाना की जरूरत के सामान और खाने-पीने की चीजों की कीमतों के घटने से थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज हुई है। ये इसका 14 महीने का निचला स्तर है। मंत्रालय के मुताबिक इससे पहले अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 2.05 फीसदी से घटकर 0.85 फीसदी पर आ गई थी, जो इसका 13 महीनों का निचला स्तर था। इससे पहले मार्च 2024 में थोक महंगाई दर 0.26 फीसदी रही थी। मार्च 2025 में यह 2.05 फीसदी पर था। जनवरी 2025, में 2.38 फीसदी थी, जबकि फरवरी 2025 में थोक महंगाई दर 2.38 फीसदी रही थी, जबकि मई 2024 में यह दर 0.53 फीसदी पर थी।

आंकड़ों के अनुसार खाने-पीने के सामानों में कटौती का असर थोक महंगाई दर के आंकड़ों के तौर पर साफ देखा जा सकता है। खाने-पीने की चीजों (फूड इंडेक्स) की महंगाई 2.55 फसदी से घटकर 1.72 फीसदी पर आ गई है। वहीं, फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -2.18 फीसदी से घटकर -2.27 फीसदी रही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 2.62 फीसदी से घटकर 2.04 फीसदी रही है।

अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेता मेलिसा हॉर्टमैन का कथित हत्यारा हिरासत में

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपरी मध्य-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मिनेसोटा राज्य में डेमोक्रेटिक राज्य प्रतिनिधि मेलिसा हॉर्टमैन की हत्या के आरोपित संदिग्ध वेंस बोल्टर को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया। वेंस की तलाश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 48 घंटे अभियान चलाना पड़ा। द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि मिनेसोटा राज्य की विधायक मेलिसा हॉर्टमैन की हत्या और दूसरे को गोली मारने के संदिग्ध वेंस बोल्टर को हिरासत में ले लिया गया है। इसी के साथ दो दिन तक चला तलाशी अभियान समाप्त हो गया। रैमसे काउंटी शेरिफ कार्यालय ने फेसबुक पर कहा कि पुलिस के अथक प्रयासों से हत्यारा अब हिरासत में है। उसने राज्य प्रतिनिधि मेलिसा हॉर्टमैन की गोली मारकर हत्या करने के बाद उनके पति पर भी हमला कर दिया। इससे पहले वह सीनेटर जॉन हॉफमैन को गोली मार चुका है। मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल कीथ एलिसन ने कहा कि संदिग्ध के पास से एक नोटबुक मिली है।

भारतीय श्रद्धालु 6 वर्षों बाद नेपाल होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकेंगे

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के साथ ही अब भारतीय नागरिकों को नेपाल के रास्ते तिब्बत के कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति दी गई है। चीन की सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की अनुमति दे दी है। इसके लिए नेपाली पर्यटन व्यवसायियों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। सन 2020 में कोरोना महामारी और उसके बाद भारत और चीन की सेना के बीच गलवान में हुई झड़प के बाद चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा अनुमति को रद्द कर दिया था। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनो से कूटनीतिक और राजनीतिक संवाद होने के बाद स्थिति सामान्य हुई है। इसके बाद चीन की सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की अनुमति दे दी है। तिब्बत के ल्हासा में रहे नेपाली काउंसलर विभाग के मुताबिक मानसरोवर यात्रा की अनुमति के लिए अब पुलिस सर्विस सेंटर से पत्र आना बाकी है।बताया गया है कि अगले सोमवार से भारतीय नागरिकों के लिए कैलाश यात्रा की शुरूआत हो सकती है। नेपाल में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले पर्यटन व्यवसायियों की संस्था एसोसिएशन आफ कैलाश टूर ऑपरेटर के अध्यक्ष विनोद नहर्की ने बताया कि नेपाल से इस वर्ष 20000 भारतीय नागरिकों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कोटा तय किया गया है।

अमिताभ कांत ने जी-20 के शेरपा पद से दिया इस्तीफा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

अमिताभ कांत ने जी-20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनको भारत के जी-20 शेरपा के रूप में जुलाई, 2022 में नियुक्त किया गया था। अमिताभ कांत की नियुक्ति भारत की ओर से जी-20 की अध्यक्षता संभालने से कुछ महीने पहले की गई थी। उन्होंने 45 वर्ष की अपनी सरकारी सेवा के दौरान कई कार्यभार संभाले हैं।

अमिताभ कांत ने सोमवार को 'एक्स' पोस्ट पर लिखा है कि नए अवसरों को तलाशने और जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया है। अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने भारत के जी-20 शेरपा के रूप में अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे कई विकासात्मक पहलों को आगे बढ़ाने और भारत की वृद्धि, विकास और प्रगति में योगदान करने का अवसर दिया।

उन्होंने आगे लिखा है कि मैं अपने सभी सहकर्मियों, साथियों और मित्रों का उनके धैर्य, समझ और समर्थन के लिए आभारी हूं। अब मैं मुक्त उद्यम, स्टार्टअप, थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थानों को सुविधा और समर्थन देकर विकसित भारत की ओर भारत की परिवर्तनकारी यात्रा में योगदान देने के लिए तत्पर हं। इस अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी लिंक्ड इन पोस्ट संलग्न है।

अमिताभ कांत ने अपने करियर के महत्वपूर्ण मील के पत्थरों पर प्रकाश डालते हुए 2023 में भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी को याद किया। उन्होंने कहा, 'भारत ने अफ्रीकी संघ को जी-20 में सफलतापूर्वक शामिल किया, जिससे वैश्विक समानता और वैश्विक दक्षिण की आवाज के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरी हुई।'

यूपी में दिव्यांगजन को मिलेगा समुचित सहारा, योगी सरकार लेगी पुनर्वास केंद्रों की जिम्मेदारी

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

फोटोः हि.स.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने की दिशा में पहल की है। प्रदेश में स्थापित 38 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को मजबूत करने के लिए सरकार ने इन केंद्रों को राज्य के वित्तीय संसाधनों से संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस कदम से न केवल इन केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि हजारों दिव्यांगजनों को बेहतर पुनर्वास सेवाएं भी मिल सकेंगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 38 डीडीआरसी में से केवल 5-6 केंद्रों को ही भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है। वहीं, एक केंद्र, जो जनपद अम्बेडकर नगर में स्थित है, एनटीपीसी द्वारा अपने संसाधनों से संचालित किया जा रहा है। इन केंद्रों को लेकर विभाग ने सुझाव दिया है कि इनका संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किया जाए। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तावित किया गया है। यह कदम उन दिव्यांगजनों के लिए राहत लेकर आएगा, जो इन केंद्रों के माध्यम से पुनर्वास, प्रशिक्षण और सहायता की उम्मीद रखते हैं।

डीडीआरसी को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से दिव्यांगजनों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर ह्यदिव्यांग पुनर्वास केंद्रोंह्ण की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जाए ताकि पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकें। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर जिले में मौजूद डीडीआरसी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें और दिव्यांगजनों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले। हर दिव्यांग व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल हो। इन केंद्रों को मजबूत कर योगी सरकार उनके लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रख रही है।

जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य सेवाएं, कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। हालांकि, कई केंद्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे थे। योगी सरकार का यह निर्णय इन केंद्रों को नई ऊर्जा देगा। इससे न केवल केंद्रों की सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। अब तक प्रदेश में 15 लाख दिव्यांगजन यूडीआईडी पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश को यूनिक आईडी कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं।

अर्जुन बाबूटा ने शूटिंग लीग ऑफ इंडिया के लॉन्च पर कहा, अब इस खेल को मिलेगा उसका हकदार सम्मान

2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने शूटिंग में तीन पदक जीतकर रचा था इतिहास

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

शूटिंग लीग ऑफ इंडिया (एसएलआई) की पहली सीजन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और देश के निशानेबाज इस अनोखे कॉन्सेप्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) द्वारा शुरू की जा रही इस लीग का उद्देश्य शूटिंग स्पोर्ट की बढ़ती लोकप्रियता और अंतरराष्ट्रीय मंच पर हालिया सफलताओं को और मजबूती देना है।

2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने शूटिंग में तीन पदक जीतकर इतिहास रचा था और हाल ही में अर्जुन बाबूटा और आर्या बोर्से की जोड़ी ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप (राइफल/पिस्टल) में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत की निरंतर श्रेष्ठता को दोहराया।

'मैं हमेशा कार्य पर ध्यान देने में विश्वास करता हूं, परिणाम की अपेक्षा नहीं करता

ओलंपियन अर्जुन बाबूटा का मानना है कि यह लीग इस खेल की दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा, 'हर कोई इस लीग को लेकर बहुत उम्मीदें रखता है। हमारे मन में जितनी कल्पनाएं चल रही हैं, उतनी शायद किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को लेकर नहीं हुईं। मेरा मानना है कि इस तरह की लीग से खेल को हर स्तर पर बढ़ावा मिलेगा और यह अपने हकदार पहचान तक पहुंचेगा। अब हम बस इसके अगले कदमों का इंतजार कर रहे हैं।'

अपने शांत स्वभाव और अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले अर्जुन ने एक आधिकारिक बयान में आगे कहा, 'मैं

फोटोः हि.स.

हमेशा कार्य पर ध्यान देने में विश्वास करता हूं, परिणाम की अपेक्षा नहीं करता। मैं शूटिंग का आनंद लेता हूं और मेरा ध्यान उसी पर रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष सोच से खुद को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकता है, तो वह भी अच्छा है।' हालांकि शूटिंग मुख्यतः व्यक्तिगत खेल है, लेकिन यह फ्रेंचाइजी आधारित लीग खिलाड़ियों को टीम माहौल में खेलने का मौका देगी। अर्जुन बाबूटा इस फॉर्मेट से पहले ही परिचित हैं, क्योंकि वह जर्मनी की प्रतिष्ठित शूटिंग बुंदेसलीगा में एक क्लब के लिए खेल चुके हैं।

उन्होंने बताया, 'मैं जर्मनी की टीम लीग का हिस्सा रह चुका हूं और वहां के सिस्टम से परिचित हूं। टीम का हिस्सा बनना एक अलग अनुभव होता है - यह रोमांचक होता है, दबाव भी कम होता है और खेल का आनंद भी आता है। दर्शकों के लिए भी यह फॉर्मेट बेहद मनोरंजक साबित होगा।'

आईएसएसएफ द्वारा इस लीग के आयोजन के लिए 20 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। लीग में पिस्टल (10 मीटर, 25 मीटर), राइफल (10 मीटर, 50 मीटर 3 पोजिशन) और शॉटगन (ट्रैप और स्कीट) के मिक्स्ड टीम इवेंट्स होंगे, जिन्हें एनएआरआई की तकनीकी समिति से मंजूरी मिल चुकी है।

बाबूटा को विश्वास है कि इस लीग से खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता मजबूत होगी और आम जनता को भी खिलाड़ियों की सोच और संघर्षों को समझने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा, 'लोगों को सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि असल जीवन में यह जानने का मौका मिलेगा कि एक एथलीट किस तरह मेहनत करता है, किस सोच के साथ आगे बढ़ता है। हर इंसान की अपनी चुनौतियां होती हैं, और अगर हमारी कहानियां उन्हें प्रेरित कर सकें तो यह इस लीग की बड़ी उपलब्धि होगी।'

लीग में खिलाड़ियों को चार श्रेणियों में बांटा जाएगा – एलीट चैंपियंस, वर्ल्ड एलीट, नेशनल चैंपियंस और जूनियर व यूथ चैंपियंस। बाबूटा का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने से भारतीय निशानेबाजों को मानसिक मजबूती और नई रणनीतियों का लाभ मिलेगा।

एमएलसी 2025: टेक्सास सुपर किंग्स ने लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स को हराया, दर्ज की लगातार दूसरी जीत

एजेंसी (हि.स.)
डलास

फोटोः हि.स.

टेक्सास सुपर किंग्स (टीएसके) ने मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए सोमवार (भारतीय समयानुसार) लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स (एलएकेआर) को बड़े अंतर से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद टीएसके ने एक बार फिर लगभग वही स्कोर खड़ा किया जो उन्होंने पिछले मुकाबले में किया था और अंततः बाजी अपने नाम की।

इस बार बल्लेबाजी में किसी एक खिलाड़ी का बड़ा योगदान नहीं रहा, बल्कि संयुक्त प्रयास देखने को मिला। टीम के असली हीरो गेंदबाजी में नजर आए – एक बार फिर एडम मिल्ने और युवा स्पिनर नूर अहमद चमके। LAKR की ओर से पहली उल्लेखनीय साझेदारी एलेक्स हेल्स (17 गेंद में 25 रन) और उन्मुक्त चंद (23 गेंद में 22 रन) के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई, जिन्होंने 27 रन जोड़े। हालांकि रन गति बेहद धीमी रही। इसके बाद उन्मुक्त चंद ने मैथ्यू ट्रॉम्प (12 गेंद में 23 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 28 रन जोड़े, लेकिन फिर भी टीम को जरूरी रफ्तार नहीं मिल सकी।

एडम मिल्ने ने शुरूआत में आंद्रे फ्लेचर को आउट कर पहली सफलता दिलाई और अंत में तनवीर सांगा को आउट कर छअडफकी पारी समेट दी। मिल्ने ने 3.1 ओवर में केवल 8 रन देकर 2 विकेट झटके। वहीं नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, मैथ्यू ट्रॉम्प और नितीश कुमार को आउट कर 25 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए।

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए टीएसके की शुरूआत अच्छी रही। टॉप ऑर्डर में डेवोन कॉनवे (22 गेंद में 34 रन) और साइटेजा मुक्कामल्ला (22 गेंद में 31 रन) ने कप्तान फाफ डु प्लेसिस के जल्दी आउट होने के बाद पारी को संभाला। इन दोनों ने सिर्फ 5.1 ओवर में 57 रन जोड़े। आठ ओवर के बाद स्कोर 74/1 था और टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी।

इसके बाद डेरिल मिचेल (33 गेंद में नाबाद 36 रन), शुभम रंजन (19 गेंद में 24 रन) और डोनोवन फेरेरा (16 गेंद में नाबाद 32 रन) ने पारी को मजबूत अंजाम दिया। खासकर फेरेरा ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। ट्रॉम्प भी छअडफकी ओर से 191.66 की स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला।

इस जीत के साथ टेक्सास सुपर किंग्स ने टूर्नामेंट में अब तक दो में से दो मैच जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है।

संक्षिप्त स्कोरः

टेक्सास सुपर किंग्स 181/4 (मिचेल 36*, कॉनवे 34, फेरेरा 32*, मुक्कामल्ला 31; सांगा 2/32)

लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स 124 ऑलआउट (वैन शाल्कवाइक 27; नूर 4/25, मिल्ने 2/8, विएग 2/25)

टेक्सास सुपर किंग्स ने 57 रन से जीत दर्ज की

आर्मंड डुप्लांटिस ने 12वीं बार पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, स्टॉकहोम में रचा इतिहास

एजेंसी (हि.स.)
स्टॉकहोम

फोटोः हि.स.

स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को डायमंड लीग प्रतियोगिता के दौरान डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए 12वीं बार नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया।

अमेरिका में जन्मे इस दो बार के ओलंपिक चैंपियन ने फरवरी में बनाए अपने ही रिकॉर्ड को एक सेंटीमीटर से बेहतर किया। स्टॉकहोम के ऐतिहासिक ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने पहले ही प्रयास में यह कारनामा कर दिखाया। शानदार मौसम और घरेलू दर्शकों का उत्साह उनके प्रदर्शन को और ऊंचाई देने वाला साबित हुआ।

डुप्लांटिस ने प्रतियोगिता से पहले ही वादा किया था कि वे रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। उनके नाम की उद्घोषणा होते ही पूरा स्टेडियम तालियों और जोश से गूंज उठा। दर्शकों का उत्साह उनके हर प्रयास में झलकता रहा, और डुप्लांटिस ने भी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शानदार प्रदर्शन किया।

ऑस्ट्रेलिया के कर्टिस मार्शल ने उन्हें चुनौती देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे अधिकतम 5.90 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाए। छह मीटर की बाधा पार करने में वे तीन बार असफल रहे, जिससे मैदान डुप्लांटिस के लिए खुल गया।

जब बार को 6.28 मीटर पर रखा गया, तो डुप्लांटिस ने अपने पहले प्रयास में ही उसे पार करते हुए स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ा दी।

फीफा क्लब विश्व कप में पीएसजी की धमाकेदार शुरूआत, एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से हराया

पैसाडेना (लॉस एंजेलिस)। हाल ही में चैंपियंस लीग जीतने वाली पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने फीफा क्लब विश्व कप के अपने पहले मैच में स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से करारी शिकस्त दी। यह मुकाबला रविवार को रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया, जहां फ्रांसीसी क्लब ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा। गर्म और धूप भरे माहौल में खेले गए इस मैच में पीएसजी को अपने दो अहम खिलाड़ी – उस्मान डेम्बेले और ब्रैडली बारकोला – की कमी खलने नहीं दी। शुरूआत से ही पीएसजी ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और 19वें मिनट में फाबियन रुइज ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। पहले हाफ में एटलेटिको की ओर से एकमात्र स्पष्ट मौका एंटोइन ग्रिजमैन के पास आया, लेकिन उनका शॉट सीधे डोनारुमा के हाथों में गया। इसी मौके से पीएसजी ने तेज काउंटर अटैक किया और विटिन्हा ने 2-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ की शुरूआत में एटलेटिको ने कोके को मैदान में उतारा, लेकिन इससे टीम की रफ्तार में कोई खास बदलाव नहीं आया।

भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना के खिलाफ झोंकेगी पूरा दमखम

एजेंसी (हि.स.)
लंदन

फोटोः हि.स.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करीबी हार के बाद अब भारतीय महिला हॉकी टीम एफआईएच प्रो लीग 2024-25 (महिला) के लंदन चरण में वर्ल्ड नंबर 2 अर्जेंटीना के खिलाफ होने वाले मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों टीमें 17 और 18 जून को ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर लंदन में आमने-सामने होंगी।

एफआईएच प्रो लीग (महिला) अंक तालिका में भारत इस समय 9 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि अर्जेंटीना 12 में से 7 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर काबिज है। टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी मुकाबलों को लेकर एक बयान में कहा, 'अर्जेंटीना दुनिया की नंबर 2 टीम है और उनका अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। हम जानते हैं कि उन्हें हराना आसान नहीं होगा, लेकिन हम पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे और दोनों मुकाबलों में अपना शत-प्रतिशत देंगे। टीम ने अर्जेंटीना को टक्कर देने के लिए कई रणनीतियों पर काम किया है।'

उपकप्तान नवनीत कौर ने कहा, 'जैसा कि आपने देखा, टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कड़ी टक्कर दी थी और हम वही रवैया अर्जेंटीना के खिलाफ भी दिखाएंगे। उनके खिलाफ जीत से न सिर्फ अंक मिलेंगे, बल्कि बेल्जियम और चीन के खिलाफ एंटवर्प व बर्लिन में होने वाले मुकाबलों से पहले टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।' भारतीय महिला टीम अर्जेंटीना के खिलाफ पहला मुकाबला 17 जून को और दूसरा 18 जून को खेलेगी।

हायरॉक्स इंडिया ने 2025-26 सीजन का पूरा कैलेंडर जारी किया

नई दिल्ली। दुनिया भर में मशहूर फिटनेस रेस हायरॉक्स ने भारत के लिए 2025-26 सीजन (जुलाई 2025 से जून 2026) का अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस ऐलान के साथ भारत में हायरॉक्स की पहली पूर्ण सीजन की शुरूआत हो रही है, जो देश में फिटनेस संस्कृति को एक नई पहचान देने जा रही है। मुंबई में इस साल की शुरूआत में सफल डेब्यू के बाद अब हायरॉक्स इंडिया तीन प्रमुख शहरों में अपने कार्यक्रम आयोजित करेगा, जो इस प्रकार है। यह भारत में हायरॉक्स का पहला फुल-सीजन होगा, जो देश में इसके दीर्घकालिक विकास और व्यापक क्षेत्रीय भागीदारी की नींव रखेगा। हायरॉक्स इंडिया के प्रमुख दीपक राज ने कहा, 'यह भारत का हायरॉक्स सीजन है। हम एक मल्टी-सिटी कैलेंडर के साथ देशभर में लौट रहे हैं, जो हर कोने के फिटनेस प्रेमियों को आमंत्रित करता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हम एक ऐसी फिटनेस कम्युनिटी बना रहे हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक भी है और समावेशी भी।'

महिला विश्व कप 2025: भारत-पाक मुकाबले की तारीख तय

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। टूर्नामेंट की शुरूआत 30 सितंबर को होगी, जहां मेजबान भारत की टीम बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में श्रीलंका से भिड़ेगी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का राउंड-रॉबिन चरण 26 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले 29 और 30 अक्टूबर को खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।

महिला विश्व कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर. प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा।

भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच अब तक 11 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं और सभी में भारत ने जीत दर्ज की है। पिछली भिड़ंत 2022 विश्व कप में माउंट माउंगानुई (न्यूजीलैंड) में हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया था।

माध्यमिक शिक्षक के 1375 पदों पर भर्ती

18 जून से शुरू होगा पंजीकरण

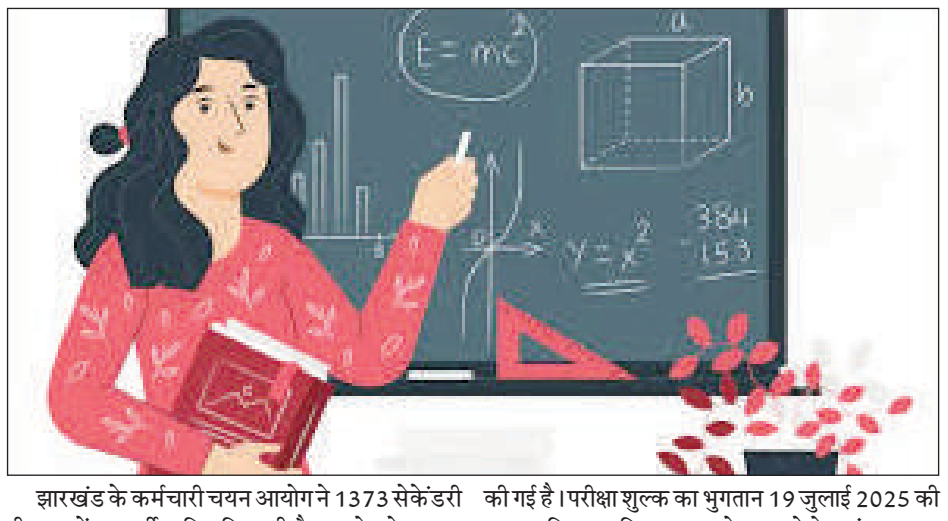

झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग ने 1373 सेकेंडरी टीचर पदों पर भर्ती अधिसूचित की है। आयोग ने इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट -ssc.jharkhand.gov.in. पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नोट करें सभी महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2025 तय की गई है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 19 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि तक किया जा सकेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए 21 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों के लिए 23 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नंबर को छोड़कर किसी भी गलत जानकारी को संशोधित करने के लिए करेक्शन विंडो लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता

आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक (Class 9th-12th) स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित पोस्ट ग्रेजुएट तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड/बी.ए.एड./बी.एससी.एड. डिग्री होनी चाहिए।अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से संबंधित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ पोस्ट ग्रेजुएट तथा तीन वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड-एमएड डिग्री होनी चाहिए।पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर चेक करें। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयुसीमा श्रेणीवार निम्न प्रकार है- ■अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 40 वर्ष ■अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरूष) - 42 वर्ष ■ महिला (जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी)- 43 वर्ष ■अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)- 45 वर्ष ■अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 45 वर्ष ■आयुसीमा की गणना 01 अगस्त 2025 के हिसाब से की जाएगी।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में 266 प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने प्रशासनिक अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल-I) के पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in. पर 3 जुलाई, 2025 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चरण-I ऑनलाइन परीक्षा 20 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जबकि चरण-II ऑनलाइन परीक्षा 31 अगस्त, 2025 को आयोजित होने की संभावना है। भर्ती अभियान का उद्देश्य 266 रिक्तियों को भरना है।

आवेदन शुल्क

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के आवेदकों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये लागू होंगे।

रिक्ति विवरण

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
डॉक्टर (एमबीबीएस)	10+4 = 14	एमबीबीएस/एमडी/एमएस या पीजी मेडिकल डिग्री
लीगल	20	कानून में स्नातक/परास्नातक
फाइनेंस	20+1 = 21	चार्टर्ड अकाउंटेंट/कोस्ट अकाउंटेंट या बीकॉम/एमकॉम
इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी	20	इंजीनियरिंग में स्तनाक/परास्नातक
ओटोमोबाइल इंजीनियर्स	20+1 = 21	इंजीनियरिंग में स्तनाक/परास्नातक
सामान्यज्ञ	170	स्नातक/परास्नातक
	कुल पद	266

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षण, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा दो चरणों में होगी। पहले प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

आवेदन करने के चरण

(•) सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in. पर जाएं। (•) होमपेज पर, 'भर्ती - प्रशासनिक अधिकारियों (सामान्य और विशेषज्ञ) की भर्ती 2024-25' पर जाएं। (•) अपना पंजीकरण कराएं और आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। (•) फॉर्म भरें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। (•) भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें।

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू

संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा - मुख्य के लिए पंजीकरण सोमवार से शुरू हो गया हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को यूपीएससी के आधिकारिक पोर्टल - upsc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन विंडो 16 जून से 25 जून, 2025 तक खुली रहेगी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले कुल 14161 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, इन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 25 मई 2025 को किया गया था। यह परीक्षा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में भर्ती के लिए पहली चरण की स्क्रीनिंग प्रक्रिया है।

इस दिन होगी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

यूपीएससी कैलेंडर के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 22 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाली है। यूपीएससी सिविल सेवा 2025 परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार की सेवाओं और विभागों में 979 रिक्तियां भरी जाएंगी। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (क्कार), भारतीय पुलिस सेवा (क्कर) और भारतीय विदेश सेवा (क्कह) शामिल हैं।

आवेदन शुल्क

सभी आवेदकों को सीएसई मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए 200 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

महिलाओं, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों के लोगों को वैध दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि लागू हो, तो उम्मीदवार लेखक, किसी सहायक उपकरण या प्रश्न पत्र की आवश्यकता के बारे में अपने विवरण को बड़े फॉन्ट में अपडेट कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल लिया है या उनके मैट्रिकुलेशन से अलग नाम है, वे इस विंडो के दौरान अपना गजट नोटिफिकेशन जमा कर सकते हैं।

यूपीएससी सीएसई मेंस पंजीकरण

किसी भी प्रश्न के मामले में उम्मीदवार शाहजहां रोड, नई दिल्ली स्थित यूपीएससी सुविधा काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टेलीफोन के माध्यम से भी सुविधा काउंटर से संपर्क कर सकते हैं।

यूजीसी नेट में सफलता चाहिए तो तथ्यों से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर दें ध्यान

भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलो बनने की चाह रखने वाले लोगों के लिए यूजीसी नेट में सफल होना जरूरी होता है। आधिकारिक सूचना के अनुसार यूजीसी नेट (जून) की परीक्षा आगामी 25 से 29 जून तक आयोजित की जाएगी। अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता और पढ़ने के तरीके में बदलाव लाना होगा। आपको तथ्यों से ज्यादा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। चाहे आप पहली बार परीक्षा दे रहे हों या फिर दोबारा परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहे हों, बिना कारगर रणनीति बनाए इस परीक्षा में आपको सफलता मिलना मुश्किल है।

'हाइपरफोकस हैक' तकनीक

तैयारी के दौरान लगातार पढ़ाई करना आपको दिमागी रूप से थका देता है। ऐसे में यह तकनीक कारगर साबित होती है। इसमें आप चालीस मिनट तक किसी टॉपिक को पूरा ध्यान लगाकर पढ़ें। इसके बाद पंद्रह मिनट उसे दोहराएं और फिर पांच मिनट छोटे ब्रेक, जैसे चलना, स्ट्रेच करना, अंतरिक्ष में देखना, आदि लें। यह तकनीक आपको न सिर्फ थकने से बचाती है, बल्कि उबाऊ और कठिन विषयों को पढ़ना आसान और रुचिकर बनाती है।

सवालों के उद्देश्य को समझें

अभ्यास प्रश्नों को हल करते समय, खुद को उस परीक्षक के रूप में देखें, जिसने उस प्रश्न को बनाया होगा। खुद से पूछें कि यह प्रश्न क्यों पूछा गया? किस अवधारणा का परीक्षण किया जा रहा है? इसे किन सामान्य गलतफहमियों को सामने लाने के लिए डिजाइन किया गया है? यह आपकी सोच को केवल सही उत्तर खोजने के बजाय सवाल में छिपे उद्देश्य और तर्क को समझने की ओर ले जाता है, जिससे आप कठिन से कठिन सवालों के जवाब भी आसानी से देने में सक्षम हो पाते हैं।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' से लोकतंत्र को मिलेगा नया आयाम: मुख्यमंत्री

संयुक्त संसदीय समिति ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर अध्ययन दौरा के दौरान की विभिन्न बैठकें

- हरियाणा सरकार का 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए सैद्धांतिक समर्थन
- 'वन नेशन, वन इलेक्शन' समय की मांग और जनता की भावना: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत, श्रेष्ठ भारत की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सशक्त और समन्वित लोकतंत्र की दिशा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। हरियाणा सरकार इस पहल का सैद्धांतिक समर्थन करती है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से देश को बहुआयामी लाभ मिलेंगे।

मुख्यमंत्री सोमवार को न्यू चंडीगढ़ में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह संयुक्त संसदीय समिति संविधान (129वां) संशोधन विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अध्ययन दौरे पर है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सांसद पी.पी. चौधरी सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' लागू होने से लोकतंत्र में बड़ा सुधार होने वाला है। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव कराए जाने से विकास कार्य बाधित होते हैं, प्रशासनिक मशीनरी चुनावों में व्यस्त हो जाती है और आम-जन पर इसका सीधा असर पड़ता है। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए बताया कि बीते एक वर्ष में हरियाणा ने तीन बड़े चुनावों का सामना किया। इनमें मार्च से जून 2024 तक लोकसभा चुनाव, अगस्त से अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव और फरवरी से मार्च 2025 तक नगर निकाय चुनाव हुए। इन सभी चुनावों की आचार संहिता के चलते राज्य में विकास कार्यों की गति प्रभावित रही। प्रशासनिक मशीनरी इसका प्रत्यक्ष असर झेलना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, चुनावों पर होने वाला व्यय भी अत्यधिक होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' न केवल संसाधनों की बचत करेगा बल्कि जनता की भी भावना है कि चुनाव एक साथ हों ताकि समय और धन की बर्बादी रुके। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आमजन की भागीदारी भी और अधिक बढ़ेगी। इसलिए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के विषय पर सभी को एक मत से समर्थन करना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि चुनावों की तिथियों का निर्धारण करते समय कृषि कार्यों, त्योहारी सीजन, विवाह सीजन, सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बार-बार चुनाव से मतदाताओं का रुझान भी कम हो जाता है, जिससे मतदान प्रतिशतता प्रभावित होती है। यदि चुनाव पांच वर्षों में एक बार होंगे, तो मतदाताओं में नया उत्साह देखने को मिलेगा। इससे लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा और जनभागीदारी बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना संभव होगा, जिससे मतदाता जागरूकता अभियानों में एकरूपता, प्रशासनिक तैयारी में समन्वय और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक में संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भर्तृहरि महताब, ईटी मोहम्मद बशीर, विजय कुमार हांसदा, येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, घनश्याम तिवाड़ी, पी. विल्सन, चंदन चौहान, मनीश तिवारी, अनिल यशवंत देसाई, डॉ. के लक्ष्मण, साकेत गोखले, बाँसुरी स्वराज और छोटे लाल के अलावा, हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

कुलभूषण गोयल आल इंडिया मेयर काउंसिल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत

संवाददाता
पंचकूला

दो दिवसीय आल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक में हरियाणा की कमान पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल को सौंप दी गई। बैठक में हरियाणा इकाई का गठन करने पर चर्चा हुई, तो करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता ने प्रस्ताव रखा कि कुलभूषण गोयल को प्रधान बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी मेयरों ने समर्थन कर दिया। आल इंडिया मेयर काउंसिल की अध्यक्ष माधुरी अतुल पटेल, महासचिव उमाशंकर गुप्ता सहित अन्य ने कुलभूषण गोयल को बधाई दी। कुलभूषण गोयल ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हरियाणा के मेयरों के मुद्दों को सरकार से उठाएंगे। हरियाणा में वैसे मेयरों को अधिकार एवं बजट की कोई कमी नहीं है। विकास की गति को पूरी तेज से आगे ले जा रहे हैं। कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी, करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता सहित अन्य ने भी कुलभूषण गोयल को बधाई दी।

बिजली और पानी की भारी किल्लत पर लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ लगाए नारे

मोहाली। मोहाली के लोग इस समय एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहाँ लंबे और बिना पूर्व सूचना के लगने वाली बिजली कटौतियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। गर्मी की तपिश में न केवल बिजली की अनियमित आपूर्ति ने लोगों को परेशान किया है, बल्कि पानी की सप्लाई भी पूरी तरह से ठप हो जाने के कारण लोग अपनी बुनियादी जरूरतों से भी वंचित हो गए हैं। इस विरोध के चलते आज गांव सोहाना के नगर निवासियों द्वारा एयरपोर्ट रोड पर जोरदार धरना दिया गया। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। उनकी माँग थी कि बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तत्काल मुहैया करवाई जाएं। इस धरने के दौरान विशेष रूप से शिरोमणि अकाली दल हल्का मोहाली के मुख्य सेवक परविंदर सिंह सोहाना भी पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुफ्त बिजली के वादे अब हर जगह आम आदमी पार्टी के चुनावी पोस्टरों की तरह झूठे लगने लगे हैं।

समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें अधिकारी: उपायुक्त

- सोमवार व वीरवार को प्रातः 10 से 12 बजे तक हो रहा समाधान शिविर का आयोजन

संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में गांव श्यामटू के ग्रामीणों की सामुदायिक केंद्र के पास शामलात जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीडीपीओ को मामले की जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि समाधान शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जिले की जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी स्वयं शिविर से जुडकर शिविरों में सुनी जा रही समस्याओं की मोनिटरिंग करते है।

उपायुक्त ने बताया कि जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार व वीरवार को उपायुक्त कार्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रापर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, नक्शे की मंजूरी, पैंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक नितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली- पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

उपायुक्त ने सोमवार को जिले के 6 लोगों की समस्याएं सुनी व संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर नगराधीश विश्वनाथ सिंह, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, आयुष विभाग, जिला परिषद, पीएचईडी विभाग, एमआई काडा विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मत्सय विभाग, पुलिस विभाग, माईनिंग, पीडब्लयूडी बीएंड आर, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, यूएचबीवीएन, नगर निगम कालका व पंचकूला के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

संक्षिप्त-समाचार

शहरों के विकास पर विशेष ध्यान दें: बंडारु दत्तात्रेय

पंचकूला। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए देशभर के मेयर्स के साथ मुलाकात की। पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल द्वारा चौखी ढाणी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलभूषण गोयल ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल को कुलभूषण गोयल की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। राज्यपाल ने कहा कि यह बहुत अच्छा अवसर है जब एक साथ मिलकर देश भर के मेयर अपने शहरों के विकास के लिए चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने शहरों में विकास की गति को तेज करने पर अधिक ध्यान देने को कहा। कुलभूषण गोयल ने राज्यपाल को बताया कि देशभर से लगभग 55 मेयर पंचकूला में भाग लेने आए और काफी अच्छी चर्चा हुई। इस अवसर राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा, विधायक शक्तिरानी शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।

राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 27 से पंचकूला में

चंडीगढ़। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता (महिला एवं पुरुष वर्ग) का आयोजन 27 जून से 29 जून तक पंचकूला में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में महिला (सीनियर वर्ग) में भार 45-48 किलोग्राम, 51 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, +80 किलोग्राम तथा पुरुष (सीनियर वर्ग) में 47-50 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, +90 किलोग्राम भार वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

पंचकूला के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं सुनवाई आज

चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यूएचबीवीएन सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 17 जून को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय पंचकूला में की जाएगी। मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुमार्ना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

पेक के छात्रों ने बाजाज टीओआरक्यू और ओएचएम चैलेंज के ग्रैंड फिनाले में मारी बाजी

चंडीगढ़। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), चंडीगढ़ के अंतिम वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्रों - सर्वज्ञ बाली, निखिल सैनी और मयंक भटनागर - ने हाल ही में बाजाज टीओआरक्यू और ओएचएम चैलेंज के ग्रैंड फिनाले में कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया और पूरे देश के फाइनलिस्ट्स के बीच न सिर्फ कैंपस विनर्स बने, बल्कि क्विज राउंड और डिजाइन थिंकिंग चैलेंज दोनों में शानदार जीत हासिल कर पहले स्थान पर रहे। नकी इस उपलब्धि पर उन्हें 30,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया और कॉलेज के डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) राजेश भाटिया द्वारा सम्मानित भी किया गया।

11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2025 के अंतर्गत तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

- आयुष योग विशेषज्ञा व पतंजली के योग शिक्षकों द्वारा करवाया गया योग प्रोटोकॉल का अभ्यास

संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में 18 जून तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन परेड ग्राउंड, सैक्टर-5 में किया गया।

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, डा0 दिलीप कुमार मिश्रा, ने बताया कि इस शिविर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2025 की तैयारियों को लेकर जिला स्तर पर मंत्रीगण, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, अन्य सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, स्कूली छात्रों एवं इच्छुक जनसाधारण को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिन परेड ग्राउंड, सैक्टर-5, पंचकूला में जिला स्तर पर जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को योग प्रोटोकॉल का अभ्यास आयुष योग विशेषज्ञा व पतंजली के योग शिक्षकों द्वारा करवाया गया जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों ने बढ-चढ कर भाग लिया।

उन्होने बताया गया कि प्रशिक्षण शिविर का आंरभ प्रार्थना मंत्र के उच्चारण से किया गया। तदोपरांत योग क्रियाओं जैसे ताडासन, वृक्षासन, पादहस्त, अर्धचक्रासन, वज्रासन, उत्तानमण्डुक, उष्ट्रासन, वक्रासन, मक्रासन, शलभासन, सेतुबंध, उत्तानपादासन, पवनमुक्त, अर्धहलासन, अनुलोम विलोम, कपालभाती, भ्रामरी का अभ्यास करवाते हुए इन यौगिक क्रियाओं द्वारा होने वाले लाभों की भी जानकारी दी गई।

सीएचबी के अलॉटियों को लिफ्ट का उपयोग करने के लिए देना होगा लागत का बराबर योगदान

चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के फ्लैट्स में अब लिफ्ट लग पाएगी। सेक्टर-51ए और सेक्टर-38 वेस्ट के फ्लैट्स के लिए स्टैंडर्ड ड्राइंग्स जारी की गई हैं हैं। लिफ्ट लगवाने के इच्छुक आवेदकों को निर्धारित फीस के साथ आवेदन करना होगा। साथ ही एस्टेट ऑफिस से भी मंजूरी लेनी होगी। सीएचबी के दिशा-निदेर्शों के अनुसार सीएचबी के अलॉटियों को लिफ्ट का उपयोग करने के लिए लागत में बराबर योगदान देना होगा। आवेदक निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त कर ही लिफ्ट लगा सकेंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) में बदलाव होने तक लागू रहेगी। तब तक अलॉटियों को लिफ्ट का डिजाइन मैन्युअल रूप से अप्रूव करवाना होगा। लिफ्ट लगाने के इच्छुक आवेदक सीएचबी की आधिकारिक वेबसाइट www.chbonline.in से संबंधित स्टैंडर्ड ड्रॉइंग डाउनलोड कर सकते हैं।

भाजपा की सरकार में प्रदेश का हर वर्ग दुखी और हताश: सुनैना चौटाला

संवाददाता
बरवाला

भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार में प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान है व्यापारी व छोटे दुकानदार दुखी हैं। इस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं हर रोज फिरौतीयां मांगी जा रही है ।फिरौती ना देने पर सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। उक्त शब्द इनैलो की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने गांव अलीपुर में पार्टी की महिलाओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहे ।उन्होंने कहा कि जिस देश में खाने पीने के सामान पर भी कर लगा दिया जाए, तो समझो कि उस देश का व्यापारीकरण हो गया है। इनैलो की महिला प्रदेश संयोजक सुनैना चौटाला सोमवार को अलीपुर में जिला सम्मेलन में पहुंची। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। सुनैना ने कहा कि अब इनेलो हल्का स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर बोलते हुए तनुजा और जिला प्रधान सुरेश चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि शीघ्र ही पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं का मजबूत संगठन खड़ा कर लिया जाएगा। 2029 में अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे।

रोष

भगवंत मान का 24 घंटे बिजली सप्लाई का वादा अधूरा: सिद्धू

मोहाली के लोग असहनीय गर्मी में बिना बिजली के रातें गुजारने को मजबूर हैं: बलबीर सिंह सिद्धू

संवाददाता
मोहाली

पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली आपूर्ति के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा, 'आज मोहाली में तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है, हर रात 8-10 घंटे बिजली कटौती हो रही है, लोग बिना बिजली के रातें गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन भगवंत मान लुधियाना में होने वाले चुनावों में अपना झूठा प्रचार करने में व्यस्त हैं।'

हाल ही में मनीष सिसोदिया द्वारा शून्य बिजली कटौती के बारे में पर किए गए ट्वीट पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा, 'इस असहनीय गर्मी में पंजाब में बिजली कटौती के कारण लोग अपनी कारों में सोने को मजबूर हैं और दिल्ली से आए मनीष सिसोदिया बेशर्मी से दावा कर रहे हैं कि पंजाब में शून्य बिजली

- आप सरकार मोहाली के लोगों को निर्बाध बिजली सप्लाई देने में बुरी तरह विफल रही है: पूर्व कांग्रेस मंत्री

कटौती है!'

मोहाली में बिजली कटौती से परेशान लोगों की ओर आप सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सिद्धू ने कहा, '6 दिन से अधिक हो गए हैं, मोहाली और आसपास के इलाकों के निवासी बिजली कटौती के कारण परेशान हैं, बिजली अधिकारियों को लिखित शिकायत के बावजूद स्थिति बदलने की बजाय हर दिन बदतर होती जा रही है।'

सिद्धू ने आगे कहा कि मोहाली एक ऐसा शहर है जहां देश भर से लोग पढ़ाई और काम करने आते हैं, 'ऐसी समस्याओं के कारण न केवल उनकी पढ़ाई-लिखाई और नौकरी मुश्किल हो

रही है बल्कि देश भर में राज्य का नाम भी बदनाम हो रहा है।' पिछले कुछ महीनों में राज्य भर में हुई बिजली कटौती की ओर ध्यान दिलाते हुए सिद्धू ने कहा, 'सिर्फ.घरों की ही नहीं, इससे पहले भी राज्य के राजिन्द्रा अस्पताल, पटियाला जैसे प्रीमियम अस्पतालों में भी बिजली कटौती के कई मामले सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार को न तो अपने लोगों की चिंता है और न ही अपने मरीजों की, उन्हें सिर्फ.अपने झूठे विज्ञापनों के जरिए वोट बटोरने की चिंता है।'

राज्य के थर्मल यूनिट की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए सिद्धू ने कहा, 'पंजाब में 15 में से 4 थर्मल यूनिट बंद हो चुकी हैं। यह बिजली संकट नहीं, बल्कि सरकार की नाकामी का सबूत है। भगवंत मान की सरकार सिर्फ.मीडिया की झूठी चमक-दमक में व्यस्त है, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है।'

सिद्धू ने भगवंत मान सरकार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, 'जहां आज पूरा पंजाब बिजली संकट में फंसा हुआ है, वहीं बिजली विभाग में कई पद खाली पड़े हैं। मजबूर कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना 18-20 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि मैं इन कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं जो हमें निर्बाध बिजली मुहैया कराने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। साथ ही मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द बिजली विभाग में खाली पड़े पदों को भरा जाए।'

सिद्धू ने अंत में कहा, 'आप सरकार को झूठा प्रचार करने की बजाय जमीनी हकीकत और लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पंजाब इस समय गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। भगवंत मान सरकार को इस मुद्दे का तुरंत समाधान निकालना चाहिए और वोट हासिल करने के लिए झूठा प्रचार नहीं करना चाहिए।'

पंचकूला और कालका में 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

संवाददाता
पंचकूला

अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था, अब 12 जुलाई 2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-1, पंचकूला और उप-मंडल न्यायालय, कालका में आयोजित की जाएगी।

लोक अदालत के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए और जनता का मार्गदर्शन करने के लिए, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के साथ-साथ मिनी सचिवालय (डीसी कार्यालय भवन) में स्थापित हेल्प डेस्क पर पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तैनात रहेंगे। ये पीएलवी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान करके वादियों और आगंतुकों की सहायता करेंगे और निपटान के लिए योग्य मामलों की पहचान करने में

मदद करेंगे। लोक अदालत से पहले, पीएलवी और पैनल अधिवक्ता कानूनी साक्षरता शिविरों और कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियों को अंजाम देंगे। इन आयोजनों के दौरान, वे लोगों को लोक अदालत प्रणाली के लाभों, यह कैसे त्वरित और लागत-मुक्त न्याय प्रदान करती है, और उन मामलों की श्रेणियों के बारे में शिक्षित करेंगे जिन्हें समझौते या आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए, पंचकूला में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार भी किया जाएगा। ये स्क्रीन लगातार लोक अदालत की तारीख, स्थान और उठाए जा रहे केस के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेंगी, जिससे जनता की भागीदारी और विवादों के शीघ्र समाधान को बढ़ावा मिलेगा।

भारद्वाज ने बताया कि लोक अदालत के दौरान सभी प्रकार के मामलों पर विचार किया जाएगा, जिसमें मुकदमे से पहले के और लंबित मामले शामिल हैं। इनमें सिविल विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी मामले, बैंक वसूली मामले, बिजली और पानी के बिल विवाद और इसी तरह के अन्य समझौता योग्य मामले शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और समयबद्ध तथा वादी-अनुकूल तरीके से सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है।